श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव : सर, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं को शिक्षित किया गया है। Out of 91 lakhs in the entire country, 12.63 लाख का आँकड़ा केवल उत्तर प्रदेश से है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जो लोग शिक्षित किए गए, उनमें से कितने लोगों को उत्तर प्रदेश में रोज़गार का अवसर मिला है? सरकार और अधिक अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री राजीव चन्द्रशेखर : सर, मैं धन्यवाद देता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

[*Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link* https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us take up the Motion of Thanks on the President's Address. Shrimati Geeta *alias* Chandraprabha to move that an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31st, 2022."

Shrimati Geeta *alias* Chandraprabha now to make her speech.

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाएः-

"राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2022 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

उपसभापति महोदय, आपने आज मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रेरक अभिभाषण पर धन्यवाद देने व समर्थन के लिए मुझे अवसर दिया गया, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, यह सदन विशाल ज्ञान का सागर और उसमें से मेरा एक छोटे से झरने की तरह अल्पज्ञान - लेकिन हां, मुझे जो संस्कार मिले हैं, मैंने आप लोगों के बीच में रहकर जो देखा है, उसी से मैंने सीखा है और सीखने की कोशिश करती हूं।

महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने और देश की 130 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना है, जो हमारे लिए प्रेरणास्त्रोत है। किसी पर कोई कटाक्ष न करते हुए देश की दशा और दिशा को तय करने वाली नीतियों व देश के समक्ष खड़ी चुनौतियों के समाधान का मार्ग बताने वाले इस अभिभाषण का आधार देश के नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास है। महोदय, देश में वर्ष 1984 के बाद वर्ष 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब कुछ लोगों को तथा सदन में बैठे हमारे कुछ साथियों को यह लगता था कि यह कैसे संभव हुआ है। वर्ष 2014 से पहले की सरकार की नाकामियों तथा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए देश की जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश दिया। हमारी सरकार द्वारा 5 वर्षों में दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लिए किए गए कार्य, देश के विकास के लिए किए गए कार्य के आधार पर वर्ष 2019 में पुनः स्पष्ट बहुमत मिला।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण तथा माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने हवाओं की भांति समान रूप से समानता के भाव से देश के प्रत्येक नागरिक के उत्थान के लिए रात-दिन कार्य किया है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक समानता। आज हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूल-मंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चल रही है। हम सभी के समक्ष इसके अनेकों उदाहरण हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 परसेंट आरक्षण देने के साथ-साथ एस.सी.,एस.टी. व ओबीसी वर्ग के लिए सरकार द्वारा अनेकों-अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कर राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। महोदय, इससे देश की अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 671 जातियों को लाभ मिलेगा। मैडिकल की तैयारी कर रहे ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के हितों को देखते हुए हमारी सरकार ने मैडिकल में ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए ऑल इंडिया कोटा 27 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

वहीं सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शामिल किया है। अनुच्छेद 338(डी) के जरिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन कर उस को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। महोदय, पहले आयोग का गठन तो किया गया था, परन्तु आयोग को नाम मात्र की शक्तियां भी प्रदान नहीं थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया यह आयोग सिर्फ कागजों में चल रहा है, परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के पिछड़े समाज के हितों को देखते हुए संवैधानिक संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कीं, इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूं।

अनुच्छेद 342(ए) के जरिये अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूचियों में व्यवस्था की गई है। आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनुच्छेद 366 (26सी) के जरिये राष्ट्रीय, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इन व्यवस्थाओं के कारण देश में केन्द्र के साथ-साथ अब राज्यों में भी ओ.बी.सी. वर्ग को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आरक्षण का नया रोस्टर लागू किया गया, जिसमें ओ.बी.सी. वर्ग के लिए सीधी भर्तियों में 27 परसेंट आरक्षण को लागू किया गया है। इसी प्रकार से देश के लगभग सभी राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग व उसके अधिकारों के लिए काम किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा पिछड़े वर्ग से जुड़े प्रावधानों को जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इस कारण से यह सब संभव हो रहा है। आज देश का पिछड़ा वर्ग माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी है तथा 2014 व 2019 की तरह आगे भी हमारी सरकार को स्पष्ट जनादेश दिलाने में अपना योगदान करता रहेगा।

यह समानता का भाव सिर्फ योजनाओं में तथा नीतियों में ही नहीं है, बल्कि यह समानता का भाव हमारी सरकार में भी देखा जा रहा है। आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओ.बी.सी. के मंत्री, 20 एस.सी., एस.टी. के मंत्री तथा जो 11 महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, यह प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि हमारे प्रधान मंत्री जी का ध्येय स्पष्ट है। हमारी सरकार देश के दलित व आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयासरत है। सरकार द्वारा एस.सी., एस.टी. एक्ट के मूल प्रावधानों को भी बहाल किया गया है। दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दलित युवाओं को उद्योग तथा रोजगार के लिए सरकार द्वारा राज्य अनुसूचित जाति विकास संस्थानों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनजातीय समाज के आर्थिक विकास के लिए 'वन-धन' जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनजातीय छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आश्रम स्कूल स्थापित किए गए हैं। आज हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को जल, जंगल, जीवन पर उनके अधिकार दिलाये जा रहे हैं।

आदरणीय उपसभापति महोदय, सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर उनके हितों की रक्षा के लिए अनेकानेक योजनाएं बनाकर उनको लाभ दे रही है। इन योजनाओं को बनाने के साथ-साथ माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार इन्हें सही ढंग से लागू भी कर रही है। पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने वर्ष 2022 में सभी को अपना आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

जब 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की बात आती है, तो मैंने डिबेट में देखा है कि विपक्ष के लोग उपहास के रूप में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' को देखते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं कि आप 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के बारे में उन महिलाओं से पूछिए, जो दूर-सुदूर गांवों में रहती हैं। उनको इसकी परिभाषा पता है कि जब बरसात का समय होता था और घर की छत गिर जाती थी, तब वे दीवारों पर पन्नी बांधकर अपनी पूरी रात काटती थीं और उस परिवार के पुरुष और लड़के पड़ोस के घरों के बरामदे में अपनी चारपाई डालकर सो जाते थे। यह परिभाषा उन गांवों की महिलाएं और बेटियां जानती हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत आज तक लगभग पौने दो करोड़ घरों का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लगभग 25 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 लाख घरों का निर्माण कराया जा चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों पर चलकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 'मुख्यमंत्री आवास योजना' से लगभग एक लाख से सवा लाख लोगों को आवास उपलब्ध करा चुके हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। देश के आम जन ने विश्वास के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी को देश की बागडोर सौंपी थी और माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी उनके विश्वास को जीवित रखते हुए लगभग हरेक क्षेत्र में देश के आम जन के हितों को देखते हुए काम किया है। जब स्वच्छ भारत की बात आती है, तब 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लगभग 70 लाख घरों में शौचालय बनाए गए तथा सात लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। जब हम शौचालयों की बात करते हैं, तो हमें याद आता है - मैंने देखा ही नहीं, बल्कि मैंने उसको जिया है कि जब बरसात का समय होता था और चारों तरफ पानी भरा होता था, उस समय जब गांव की महिलाएं एवं बेटियां शौच क्रिया के लिए जाती थीं और उनको शाम को कहीं जगह नहीं मिलती थी, तो मजबूरन वे विवश होकर सड़क के किनारे बैठकर शौच क्रिया करती थीं। उसी समय लाइट जलाते हुए वाहन निकलते थे और वे बेटियां और महिलाएं खड़ी हो जाती थीं और इंतजार करती थीं कि कब अंधेरा हो और मैं दोबारा शौच क्रिया के लिए बैठूं। इसके लिए देश आज़ाद होने के बाद किसी ने नहीं सोचा, लेकिन पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अस्मिता के साथ-साथ उनका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय काम है। मैं इस सदन के माध्यम से और महिला होने के नाते प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत उत्तर प्रदेश में भी यह अभियान अव्वल दर्जे पर रहा है। वहां शत-प्रतिशत जिले शौचमुक्त हो चुके हैं।

उपसभापति महोदय, रेल भारत के विकास का इंजन है। सरकार ने देश के नागरिकों को स्वच्छ रेल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रेल के लगभग सभी कोचेज़ में बायो-टॉयलेट के निर्माण को सुनिश्चित किया है। आज देश की रेल में 'स्वचछ भारत अभियान' का असर देखने को मिलता है। आप पहले कहीं जाते थे, तब स्टेशन्स पर और रेलों की स्थिति बहुत खराब थी। रेलों में बहुत गंदगी होती थी, उनमें बदबू आती थी। आज इसी अभियान के तहत जिस तरीके से स्वच्छता और सफाई मिलती है, यह बहुत ही सराहनीय है।

उपसभापति महोदय, खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में लगभग पांच लाख मौतों को न सिर्फ रोका गया है, बल्कि लगभग बीस करोड़ डायरिया जैसी बीमारी के मामलों से भी बचाया गया है। शौच मुक्त वातावरण के कारण प्रत्येक परिवार की लगभग 50 हज़ार रुपये की बचत भी हुई है। नहीं तो पहले इतनी बीमारियां होती थीं और परिवार में कोई न कोई बीमार होता रहता था। महोदय, देश के सामान्यजन को इन बीमारियों के कारण बहुत से संकटों का सामना करना पड़ा था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनकी इस पीड़ा को समझते हुए 14 अप्रैल, 2018 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर 'आयुष्मान भारत योजना' शुरू की है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है। इस योजना से प्रत्येक परिवार में सालाना पांच लाख तक का इलाज सरकार ने फ्री कराने का काम किया है। मुझे ध्यान है, जब मैं एक बार कहीं जा रही थी तो एक दादी मां एक लाठी लेकर चल रही थीं और कभी बैठ जाती थीं। मैंने रुककर उनसे पूछा कि अम्मा, आप कहां जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार थी, लेकिन अब मैं इतना चलने लगी हूं। उन्होंने यह कहा कि मोदी लला जो हैं, उन्होंने मुझे जो कार्ड बनाकर दिया है, उसके कारण मैं अब जीवित हो गई हूं और अब मैं पुनः इलाज के लिए जा रही हूं। इस योजना के अंतर्गत अब देश में लगभग 16 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोगों को 'आयुष्मान कार्ड' से किए जा रहे इलाज का लाभ मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग दो करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। जिस तरीके से माननीय प्रधान मंत्री जी योजनाएं लागू करके उनकी शुरुआत करते हैं, उसी तरीके से तुरंत हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन योजनाओं को धरातल पर लागू करके प्रत्येक तबके, प्रत्येक जाति, धर्म या समुदाय के सभी लोगों के लिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की जनता के कष्ट को समझा है। बहुत से लोग पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं करा पाते थे। आज वे किसी भी बीमारी का इलाज अस्पताल में करा सकते हैं।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हमारी माताओं और बहनों को भी बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता था। चूल्हे पर लकड़ी या किसी अन्य ईंधन के माध्यम से खाना बनाते समय उनके मुंह या नाक में धुआं जाने से उन्हें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस धुएं से हमारी देश की करोड़ों माताओं और बहनों की आंखों से निकले आंसुओं को 'उज्ज्वला योजना' चलाकर पोंछने का जो काम किया है, यह दूसरा कोई नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर एक बेटा समझकर या अपनी बहन समझकर या अपने को एक भाई के रूप में ही उन्होंने यह जिम्मेदारी ली है। देश की प्रत्येक महिला और बेटी इससे बहुत ही खुश है और माननीय प्रधान मंत्री जी को दुआएं दे रही है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी गैस के चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। केवल खाना बनाना ही नहीं, बल्कि इससे जो उनका समय बचता है, उससे वे अपने और भी रोज़गार के काम करती हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 8 करोड़ मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। इस योजना की शुरुआत 2016 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की थी। उज्ज्वला-1 से उत्तर प्रदेश में लगभग 1,47,28,593 माताओं और बहनों को मुफ्त सिलेंडर मिले हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उज्ज्वला-1 की सफलता को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके विस्तार के लिए उज्ज्वला-2 की

शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। इस योजना का विशेष लाभ हमारी माताओं और बहनों को मिला है। उज्ज्वला-1 के साथ-साथ उज्ज्वला-2 योजना उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री जी ने महोबा जिले से की थी और महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है।

बुंदेलखंड में हमारा औरैया जनपद भी आता है। इसलिए यह हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में जब यह योजना लागू की गई, तो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड को एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, वहां की महिलाओं के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया, यह एक बहुत ही सराहनीय काम है।

सरकार स्वास्थ्य, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ-साथ आम जन के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसी श्रेणी में सरकार द्वारा "ग्रामीण उजाला योजना" की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत देश में लगभग 60 करोड़ LED बल्बों के वितरण का लक्ष्य रखा गया और अभी तक करीब 40 करोड़ से अधिक LED बल्बों का वितरण किया जा चुका है। एक सांसद का बेटा या बेटी, एक विधायक का बेटा या बेटी, एक चेयरमैन का बेटा या बेटी और एक ग्राम प्रधान का बेटा या बेटी ही बिजली की रोशनी में पढ़ सकता है, लेकिन अब गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बेटे या बेटी को भी अधिकार है कि वह भी बिजली की रोशनी में पढ़ सके, इसके लिए इस योजना को लागू करके माननीय प्रधान मंत्री जी ने समानता दिखाई है कि लोग किसी भी धर्म के हों, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, शोषित हों या वंचित हों, उन्होंने सबके बेटे-बेटी को समान अधिकार प्रदान किया है कि उनके भी बच्चों को बिजली की रोशनी में पढ़ने का अधिकार है, इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं।

महोदय, कोरोना महामारी के कारण देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती थी। इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश, इस महामारी पर इस प्रकार से नियंत्रण करेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इस विपरीत परिस्थिति में देश ने समूचे विश्व को एक नई दिशा और राह दिखाई है। इस महामारी के बचाव के साथ-साथ इतनी बड़ी आबादी को भूखा नहीं सोने देना, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। माननीय प्रधान मंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त राशन वितरण कराया है। उन्होंने केवल राशन का ही वितरण नहीं कराया है, उस राशन के साथ-साथ दाल, चना, तेल, नमक का भी वितरण कराया है। इसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था कराई गई है कि कहीं भी, किसी भी व्यक्ति को यह महसूस नहीं हो कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह अपनी पसंद की चीज़ नहीं खा सकता है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए मजबूत बनाने के लिए आगाह किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू भी कर दिया है। वर्ष 2014 के बाद देश में लगभग 160 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो पिछले साढ़े चार वर्षों में 16 नये मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं तथा 14

मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। सरकार के द्वारा "वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज" की नीति पर कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपलब्धता को देखते हुए पूरे देश में MBBS की सीटों में बढ़ोतरी भी की है। इससे एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि देश में और प्रदेश में कहीं भी, किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 1,840 सीटें थीं, वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में 2,550 सीटें थीं, अब राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है, वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या को बढ़ाकर लगभग साढ़े चार हज़ार कर दिया गया है। महोदय, 2014 के बाद से देश में 22 नये "एम्स" का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित "एम्स" का प्रदेश की जनता पूरी तरह से लाभ उठा रही है।

कोरोना की इस महामारी में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना सभी के लिए एक बहुत बड़े संकट का विषय था। भविष्य में इस कारण से किसी संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने देश के प्रत्येक जिले के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। ये बहुत-सी जगहों पर स्थापित हो चुके हैं। कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार ने ऑक्सीजन ट्रेन संचालित की है, वायु मार्ग द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराई गई। राज्य सरकारों के साथ इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों को सही मायनों में समझते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी देश के प्रत्येक राज्य के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इतने विशाल देश में सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, परंतु इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त वैक्सीन देने की योजना बनाई और इस योजना पर काम करते हुए आज देश में लगभग 150 करोड़ वैक्सीन्स लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीन के विषय में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहाँ 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश की जनता को इस महामारी के समय मुफ्त व समय से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों की तरफ से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। इन्हीं कार्यों के कारण मैं देश की माताओं, बहनों का भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से सरकार के बीच रखना चाहती हूं। ये पंक्तियां इस प्रकार हैं :

'दुनिया के इस कठिन मंच पर,
एक प्रदर्शन मैं भी दिखाऊंगी,
अब स्वतंत्र मंच पर मैं भी अपना परचम लहराऊंगी।
उतारो चाहे मुझे जिस क्षेत्र में,
सर्वश्रेष्ठ करके दिखाऊंगी।

चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी।
गर्व से नारी ही कहलाऊंगी।
मैं जगत जननी कहलाऊंगी।'

महामहिम जी ने कहा कि 2014 के मुकाबले उनकी सरकार के प्रयासों के कारण देश के पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी की गई है। यह इसलिए की गई है कि देश की बेटियों में कुछ करने जो क्षमता थी, उसके मद्देनज़र पहली बार उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। चाहे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के माध्यम से हो या बेटा-बेटी को बराबर की समानता देते हुए महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए लाया गया विधेयक हो, चाहे तीन तलाक जैसे अन्य विषय हों, महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में सरकार को प्रोत्साहित किया है। सशक्त महिला से सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। देश में महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और सम्मान के कारण सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ समय पूर्व गृह मंत्रालय ने देश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने की अनिवार्यता कर दी है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक थाने में 1,535 महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो गए हैं। मैं आपको इसलिए बधाई देती हूं, क्योंकि जब किसी महिला और बेटी के साथ कोई अन्याय होता था, उनके साथ अत्याचार, दुराचार होता था और वे थाने में पहुंचती थीं, तो उन्हें अपनी बात कहने में संकोच होता था, लेकिन जब अधिकारी भी महिला है और फरियादी भी महिला है तो वे अपनी बात आराम से रखती हैं और उन्हें न्याय भी मिलता है। मैं इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि वे अपने देश की बेटियों और महिलाओं के लिए कितने संवदेनशील हैं।

12.00 P.M.

इसलिए मैं बार-बार उनका आभार व्यक्त करती हूँ। देश में यौन अपराधों पर रोक लगाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए 14 राज्यों में साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। आज देश आतंकवाद और दंगों से मुक्त है। माननीय उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश को कभी दंगों के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अपनी कानून-व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। जिन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है, उनकी वसूली भी उन्हीं लोगों के द्वारा की गई है। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक स्थान में महिला हेल्प डेस्क बनाई जा चुकी है। PAC में महिला बटालियन बनाई जा चुकी है। उसमें भी हमारी सरकार इसलिए बधाई की पात्र है कि उसने झलकारी बाई बटालियन, उदय देवी बटालियन और रानी अवंतीबाई लोधी बटालियन के नाम से जो महिला

बटालियन बनायी है, उसने महिलाओं का सिर ऊँचा किया है और इससे महिलाओं को सम्मान मिला है।

महोदय, इसी तरीके से महिलाओं के लिए नगरों में पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में माताओं और बहनों को सशक्त करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी विभिन्न योजनाओं के परिणामस्वरूप देश में प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ कर 1,020 यानी 1,000 पर 20 महिलाओं/बेटियों की संख्या बढ़ी है। यह देश में पहली बार देखने को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का दाखिला भी बढ़ा है। कहीं न कहीं यह कानून-व्यवस्था चुस्त होने का परिणाम है। यह सब सरकार की महिलाओं के विकास के लिए स्पष्ट नीतियों के कारण संभव हो पा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, भारत गाँवों का देश है।

श्री उपसभापति : माननीय चंद्रप्रभा जी, आप कृपया conclude करिए।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : सर, मैं बस 5 मिनट लूँगी।

श्री उपसभापति : 5 मिनट नहीं, आप केवल 2-3 मिनट में conclude करिए प्लीज़।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : जी। गाँवों के विकास के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पिछली सरकारों में हम सभी ने देखा कि लोग अपने गाँवों को छोड़ कर बड़े स्तर पर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, परन्तु हमारी सरकार की गाँवों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कारण आज लोग फिर से गाँवों की तरफ लौटने लगे हैं। सरकार द्वारा गाँवों में उनके लिए घर, शौचालय, रोजगार, शिक्षा, कृषि आधारित उद्योग की व्यवस्था की जा रही है। महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी योजनाओं में गाँवों में रह रहे गरीब, पिछड़े, दलित को प्राथमिकता दी जा रही है।

महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगी। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आइए, हम सब मिल कर एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। राजनीति के ऊपर देश में करोड़ों लोगों की आशाएँ हैं, राजनीति तो होती रहेगी, परन्तु इन आशाओं को पूरा करने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Shwait Malik to make his speech seconding the Motion. माननीय श्वेत मलिक जी, आपके पास 15 मिनट हैं, प्लीज़।

श्री श्वेत मलिक (पंजाब) : माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष जो अभिभाषण हुआ, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए

आपने और मेरी पार्टी ने मुझे सुअवसर प्रदान किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे युग पुरुष, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की जो सरकार है, उसकी उपलब्धियों के बारे में जो बात की है, तो मोदी जी के बारे में मैं यही कहूँगा किः

"मंज़िलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है ।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।"

मोदी जी के बारे में मैं आगे बोलना चाहूंगा :-

"मोदी सरकार के बढ़ते क़दम,
काम ज्यादा, बातें कम।।"

ये मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां देखते हुए यह विश्वास जताया कि 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय तक मोदी जी के हाथों एक आधुनिक भारत और विकसित भारत का निर्माण हो चुका होगा।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा)** *पीठासीन हुए*]

मोदी जी की सरकार बहुत लम्बे समय तक चलने वाली है। उसके बाद यह देश परम वैभव पर पहुंचेगा, विश्वशक्ति बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक आज़ादी का संघर्ष चला, जिसमें लाखों देशवासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वह बहुत लम्बा संघर्ष चला और उस समय हमारे देश के जो शूरवीर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मन में भारत के बारे में कुछ स्वप्न थे। वे एक आदर्श भारत चाहते थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब भारत स्वाधीन हुआ तो कांग्रेस के, विपक्षी पार्टियों के कुछ दोस्त जो वहां बैठे हैं, उनके कारण हमारा देश भ्रष्टाचार से युक्त हो गया, हमारा देश पराधीन ही रह गया, जिसके कारण जो वास्तविक आज़ादी थी, वह हमें नहीं मिली। मैं तो यह कहूंगा कि सही मायने में हमारा देश 2014 में, मोदी जी की सरकार के बनने के बाद दोबारा आज़ाद हुआ है। आपने खुद देखा कि पिछली सरकार के समय में जो भ्रष्टाचार था, वह दीमक बन कर इस देश को चाट गया था। यही कारण था कि देश के लोगों ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इससे पहले मिली-जुली सरकारें बनती थीं, क्योंकि कांग्रेस ने और मिली-जुली सरकारों ने मानो आम आदमी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। इसीलिए आम आदमी जागरूक हुआ और दशकों बाद उसने एक निर्णय लिया कि अब हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वह पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए भी बनी, क्योंकि सबने मुख्य मंत्री के रूप में मोदी जी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को देखा। वे कहते थे, 'न भ्रष्टाचार करूंगा और न करने दूंगा।' गुजरात के मुख्य मंत्री रहते हुए उनकी जो उपलब्धियां थीं, उनके कारण ही देश ने 272 सांसद चुन कर भेजे और

मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जिस कांग्रेस की सरकार के 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले लम्बित थे, उस कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आदर्श सरकार बनी। उस सरकार के कार्यकाल की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया और पांच वर्ष के बाद एक बार फिर से जब मौका आया, तो 2019 में पहले से भी अधिक, 303 सांसदों के साथ उस युगपुरुष, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों के लिए इससे बड़ा कोई और प्रमाणपत्र नहीं हो सकता। जब मोदी जी पहली बार यहां आए थे, तो आते ही सबसे पहले उन्होंने इस संविधान के मंदिर में माथा टेका था और शपथ ली थी कि अब मैं देश को बदलूंगा। मैंने स्वयं देखा है कि मोदी जी एक ऐसे आदर्श प्रधान मंत्री के रूप में आए, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और मुमकिन को यकीनी बना दिया।

हर क्षेत्र में जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों के साथ मैं आज यह समझता हूं कि पहले मोदी जी ने हमें नारा दिया था कि अच्छे दिन आयेंगे तो 2014 में हमारे विपक्षी मित्रों ने मज़ाक उड़ाया। परन्तु 2019 के चुनाव का जो परिणाम आया, जिसमें हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, उसने सिद्ध कर दिया कि देश में अच्छे दिन आ गये हैं। उस चुनाव के बाद 2020 में मोदी जी ने फिर नारा दिया कि देश को हम आत्मनिर्भर बनायेंगे। आज देश के 130 करोड़ देशवासी अपने प्रधान मंत्री जी के साथ राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर इस नारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनायेंगे।

महोदय, आज मैं याद कराऊंगा कि देश में एक भयंकर गलती हुई, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय लौह पुरुष, जो देश के गृह मंत्री रहे, मैं उन्हें नमन करूंगा, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधान मंत्री जी ने विश्व में उनकी सबसे भव्य और ऊंची प्रतिमा बनाई है - सरदार पटेल जी, जिन्हें हमारे दोस्तों ने भारत रत्न भी नहीं दिया - ऐसे लौह पुरुष गृह मंत्री, जिन्होंने देश को एकत्र किया, जो देश की सभी स्टेट्स को एक साथ लाये, परंतु एक जगह वे बेबस हो गये। उस समय के प्रधान मंत्री - मैं उन्हें आदरणीय जवाहरलाल नेहरू कहूंगा, मैं उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहूंगा, वे हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे - उन्होंने एक टैम्परेरी धारा 370 बनाई, जिसने कश्मीर प्रदेश का अलग विधान, अलग संविधान, अलग प्रधान बना दिया। जो हमारे देश के पूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हें मैं आज श्रद्धांजलि दूंगा, जिन्होंने कहा कि मैं यह नहीं मानूंगा कि इस देश में एक प्रदेश ऐसा हो, जो धारा 370 और 35(ए) धाराओं से इस देश से अलग हो जाए। इन्होंने ऐसी भयंकर धारा बना दी, जिससे कि वह एक अलग तरह का प्रदेश बन गया, वहां अलग मुख्य मंत्री बन गये। उस समय डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बाहर निकले तो उस प्रदेश में जाकर उन्होंने अपनी शहादत दे दी, अपने प्राण न्योछावर कर दिये। उन्होंने उस दिन बीज बो दिया, जिसे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी ने वटवृक्ष बनाया। आज आप देखिये कि उन्होंने धारा 370 और 35(ए) को निरस्त कर दिया। आज कश्मीर में अलग विधान नहीं है, आज कश्मीर का अलग प्रधान नहीं है। आज वह भारत का अभिन्न अंग है। कांग्रेस पार्टी से जो भयंकर भूल हुई थी, उसका निवारण किसने

किया - प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। हम सब सांसदों को कश्मीर जाने का मौका मिला है। अभी कुछ समय पहले मैं वहां गया, वहां हमारी कमिटी की मीटिंग हुई थी। कांग्रेस के मित्र और दूसरी पार्टियों के मित्र भी हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में थे। हजारों सैलानियों के कारण जब हमने डल लेक पर जाम देखा, जब वहां होटलों में कमरे नहीं मिले - तो उस समय पता लगा कि आज यह वही कश्मीर है, जिस कश्मीर को "धरती का स्वर्ग" कहा जाता है। उसे स्वर्ग किसने बनाया - वह प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह ने बनाया। ..(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री श्वेत मलिक : मैं कहता हूं कि नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को यकीनी बनाने का कार्य उन्होंने किया। एक वैश्विक महामारी कोरोना, जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, उस महामारी का हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। उस समय मोदी जी ने एक सशक्त नेतृत्व देते हुए देश में लॉकडाउन लगाया तो इन्होंने तब भी उनका मज़ाक उड़ाया था कि यह लॉकडाउन क्यों लगाया? लॉकडाउन का मतलब था कि देश में कोई नुकसान न हो, क्षति न हो, उसके लिए देश को उस वैश्विक महामारी के लिए तैयार करना है।

विपक्ष में हमारे जो दोस्त बैठे हैं, मैं आज उनसे प्रश्न करूँगा कि जो ventilator है, life saving machine है, जिसे हम जीवन रक्षक यंत्र कहते हैं, आपके कुशासन में 70 वर्षों तक केवल 16,000 ventilators थे। मोदी जी के प्रयास से एक वर्ष में 59,000 ventilators बनाये गये। यह बहुत बड़ा देश है। आज 80 करोड़ देशवासियों को जो निरन्तर भोजन मिल रहा है, जिसमें 5 किलो गेहूँ और एक किलो दाल है, वह किसने दिया? कोई गरीब भूखा नहीं सोया, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला। वह किसने उपलब्ध कराया- वह प्रधान मंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया। जो पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज दिया, ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज दिया, ताकि जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनका व्यापार खराब नहीं हो, वह किसने दिया- वह मोदी जी ने दिया। जो oxygen cylinders थे - जिनका 70 वर्षों का कुशासन रहा- मैं उनसे प्रश्न करूँगा, उसमें oxygen का भी कोई प्रबन्ध नहीं था, जोकि life saving चीज़ थी। आज आप देखिए कि लगभग दो वर्ष में हर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रबन्ध मोदी जी ने करवा दिया। उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवाये हैं। जिस शहर से मैं आता हूँ, पंजाब के अमृतसर से, उस शहर में भी ऑक्सीजन के 5 बड़े प्लांट्स मोदी जी ने लगवाये हैं। आज vaccination का देखिए तो दुनिया की सबसे सस्ती vaccine किसके प्रयास से आयी? उन्होंने यह व्यवस्था की कि vaccine को laboratories में develop करेंगे। ...(**व्यवधान**)... इस तरह से शोर करने से कुछ नहीं होगा। हम facts बोलते हैं, जो आप नहीं दे सकते। आप शोर करते रह जायेंगे, हम काम करते रहेंगे।

सर, जो vaccine बनायी गयी, Covaxin, आज मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई जी का धन्यवाद करूँगा कि 165 करोड़ देशवासियों के vaccination का ही

कारण है कि इस समय यह जो Omicron का हमला हुआ, उसमें बहुत कम क्षति हुई। उसका credit मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दूँगा, क्योंकि देश में इतनी vaccination करवायी गयी है। यहाँ PPE kits का निर्माण हुआ। आज हमारा देश दुनिया में पूरी तरह से कोरोना का मुकाबला करने के मामले में प्रथम आया है। आज मोदी जी के बारे में सारी दुनिया बोलती है, सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ। Survey बोलता है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता बन कर उभरे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह survey बोलता है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

महोदय, मैं पंजाब के बारे में बात करूँगा। ...(**व्यवधान**)... डिप्टी चेयरमैन सर, मैं पंजाब के बारे में बात करूँगा। मैं पंजाब से, अमृतसर से आता हूँ। हमारे पंजाबियों को, हमारे सिख बंधुओं को, सबको जो प्यार मोदी जी ने हमेशा दिया है, मैं उसके कुछ तथ्य आपको देता हूँ।

सबसे पहला तथ्य यह है - फिर मैं वही बात करूँगा और फिर आप कहेंगे - कि कांग्रेस के गलत निर्णय से जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो करतारपुर साहब ...(**व्यवधान**)... जो दरबार साहब, करतारपुर साहब है ...(**व्यवधान**)... जो सिखों का गुरुद्वारा है ...(**व्यवधान**)... वह जो करतारपुर साहब है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please.

श्री श्वेत मलिक : वह पाकिस्तान में ढाई किलोमीटर दूर था। ...(**व्यवधान**)... पाकिस्तान में ढाई किलोमीटर दूर जो करतारपुर साहब गुरुद्वारा था ...(**व्यवधान**)... उसको पाकिस्तान में जाने दिया। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री श्वेत मलिक : यह सिख समाज की और ...(**व्यवधान**)... गुजराती समाज की पुरानी माँग थी कि उस गुरुद्वारे के दर्शन हों, उसका दीदार हो। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री श्वेत मलिक : डिप्टी चेयरमैन सर, पहले उस गुरुद्वारे को दूरबीन से देखा जाता था। जो श्रद्धालु थे, वे किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं थे। सभी श्रद्धालु यह कहते थे कि हमें दरबार साहब के, करतारपुर साहब के खुले दर्शन हों, दीदार हों। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री श्वेत मलिक : तो जो करतारपुर साहब का गलियारा खोला ...(**व्यवधान**)... करतारपुर साहब का जो गलियारा खोला - मुझे भी प्रधान मंत्री जी के साथ वहाँ जाने का सुअवसर प्रदान किया गया, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग वहाँ गये, उस गुरुद्वारे का जो गलियारा बनाया, वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पंजाबियों के लिए बनाया।

आज हमारी जो लंगर प्रथा है-पंगत, वह हमारे गुरु साहिबान ने हमें दी है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री हरमंदिर साहब में और सभी गुरुद्वारों, मंदिरों में लंगर लगते हैं, तो प्रधान मंत्री जी ने इसे देखते हुए वहां से जीएसटी का निवारण किया। मैं इसके लिए उनका हार्दिक आभारी हूं। मैं एक और प्रश्न करूंगा, आप मुझे उत्तर दें कि Indian Institute of Medical Sciences, Indian Institute of Technology , ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : कृपया सीट पर बैठकर न बोलें। आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

श्री श्वेत मलिक : जो AIIMS , IITs और IIMs हैं, ये हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जहां से देश का विकास हो रहा है, जहां से देश विकसित हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...
आज पंजाब को 70 वर्ष के बाद अमृतसर में Indian Institute of Management मोदी जी ने दिया है। भठिंडा में इनके कुशासन के 70 वर्ष के बाद पहली बार भठिंडा को AIIMS मोदी जी ने दिया है। आज पहली बार पंजाब को IIT मोदी जी ने दी है। आज central university पहली बार पंजाब को मोदी जी ने दी है। आपने क्यों नहीं दी, आप 70 वर्ष तक कहां रहे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़-प्लीज़।...(**व्यवधान**)...

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल) : उपसभापति जी, विपक्ष का जो रवैया है, क्या वे चाहेंगे कि जब वे बोलें तो हमारे भी सांसद इसी प्रकार का हल्ला करें? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैं सबसे अपील करता हूं कि आपको मौका मिलेगा।...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयल : उपसभापति जी, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, सबको एक - दूसरे को सुनना चाहिए और जब उनकी टर्न आएगी, वे उसका rebuttal कर सकते हैं। आप अपनी टर्न में rebuttal कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का रवैया दोनों तरफ से हो सकता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्वेत मलिक : सर, ऐसा है, मैं जानकारी दे रहा हूं कि एक काली सूची बनी थी।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन यह धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है । अगर हर शब्द में व्यंग्य होगा और उन्हें कोसा जाएगा, जिन्होंने देश के लिए कार्य किए हैं, तो यहां हमारे सदस्यों को भी आपत्ति है। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्वेत मलिक : मैं जानकारी दे रहा हूं कि जो पंजाब में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप अपनी जगह पर बैठें। मेरा सबसे आग्रह है, प्लीज़ आप सब अपनी जगह पर बैठें। ...(**व्यवधान**)... माननीय आनन्द जी, मेरा आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलें और जब बोलते हैं तो एक दूसरे को सुनने का धैर्य रखें। आप वही चीजें बोलें, जिन्हें आप एक - दूसरे को धैर्यपूर्वक सुन सकते है। प्लीज़, मेरा आप सबसे आग्रह है, आप लोग बैठकर हस्तक्षेप न करें। आप बैठकर बोलेंगे तो कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्वेत मलिक : महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं कि जो काली सूची थी, हमारे बहुत से पंजाबी भाई इस काली सूची के कारण देश में नहीं आ सकते थे। तो पंजाबियों की वह एक जो मांग थी कि इस काली सूची को हटाया जाए, क्योंकि वे कई दशकों से देश से बाहर थे, देश में नहीं आ सकते थे, तो जो 312 सिख बंधु थे, उन्हें काली सूची से निवारण जिसने दिलाया, वह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिलाया। अभी हमारे पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की 550 साला जन्म शताब्दी आई, तो प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने, जहां गुरु जी रहे, एक तो उन्होंने वह करतारपुर साहेब कॉरिडोर खोला और दूसरा सुल्तानपुर लोधी में गुरु जी ने, गुरु नानक देव जी ने बहुत लंबा समय गुज़ारा था, मेरे बहुत आदरणीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि यहां पर बैठे हैं, इनके नेतृत्व में सुल्तानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी बनाना निश्चित किया। एक ट्रेन चलाई गई है, जिसमें श्रद्धालुओं को सभी जो तीर्थ स्थल हैं, उनके दर्शन कराए जायेंगे। एक stamp भी जारी की गई, साथ ही एक coin भी जारी किया गया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और लंदन में चेयर बनाई गई, जिस चेयर पर गुरु नानक देव जी की जीवनी की सारी जानकारी दी जाएगी और सभी languages में उसका translation होगा।

श्री उपसभापति : आपका समय खत्म हो रहा है। कृपया कन्क्लूड करें।

श्री श्वेत मलिक : सर, मुझे पंजाब के बारे में बोलने दीजिए। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस हाईवे को मंजूरी मिली है, जो तीर्थस्थल गुरुनगरी और माता वैष्णो देवी से संबंधित है। इससे अमृतसर से दिल्ली जाने में केवल चार घंटे लगेंगे और अमृतसर से कटरा जाने में केवल ढाई घंटे लगेंगे। अमृतसर-फिरोजपुर रेलवे लिंक, जो alternative है, इसके लिए मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी को याद करूँगा, मैंने इसके लिए प्रधान मंत्री जी को निवेदन किया था, जेटली जी को निवेदन किया था। अमृतसर-फिरोजपुर रेल लिंक के लिए 299 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह 6 स्टेट्स से संबंधित है। यह लिंक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात को कनेक्ट करेगा।

जहाँ तक 'किसान सम्मान निधि' की बात है, इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस मद में quarterly 20 हज़ार करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, चूँकि पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, इसलिए यह पंजाब को भी मिल रही है। पिछले समय में किसान को नीम कोटेड यूरिया लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए किसान पैसे लेकर जाते थे, तो उनको लाठियाँ खानी पड़ती थीं। आज नीम कोटेड यूरिया सबको आसानी से उपलब्ध है। आज पंजाब के किसान को 'फसल बीमा योजना' का लाभ मिल रहा है। वहाँ soil testing की सुविधा उपलब्ध है। किसान के खेत की soil में क्या deficiency है - आज यह जानकारी वहाँ के किसान को मिल रही है।

प्रधान मंत्री जी ने मुझे जलियांवाला बाग ट्रस्ट का ट्रस्टी भी बनाया, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 70 वर्ष के बाद, वे शहीद, जिनकी आत्माएँ वहाँ विश्राम कर रही हैं, उनको सम्मान मिला। प्रधान मंत्री जी ने वहाँ के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए दिए। माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ने उसका विकास कराया।

श्री उपसभापति : आपका समय खत्म हो रहा है, इसलिए अब आप conclude कीजिए।

श्री श्वेत मलिक : सर, मेरे पास मेरी पार्टी का दिया हुआ समय है।

श्री उपसभापति : यहाँ पर आपकी पार्टी की तरफ से आपके लिए जो समय दिया गया है, उसी के अनुसार मैं आपको यह कह रहा हूँ।

श्री श्वेत मलिक : सर, मैं सिर्फ पाँच मिनट लूँगा।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप अपनी बात conclude करें।

श्री श्वेत मलिक : सर, प्रधान मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को लेकर जो शपथ खाई थी कि न भ्रष्टाचार करूँगा और न भ्रष्टाचार करने दूँगा; पहले 85 पैसे दलाल खा जाते थे और 15 पैसे लाभार्थी को मिलते थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि फिर ये चिल्लाएँगे।

श्री उपसभापति : कृपया आप चेयर को सम्बोधित करते हुए अपनी बात कहिए।

श्री श्वेत मलिक : 'प्रधान मंत्री जन-धन योजना' के तहत 43 करोड़ खाते खोले गए हैं और लाभार्थियों के खाते में direct benefit transfer हो रहा है। इस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। आज ऐसे बहुत से बड़े-बड़े लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने काले धन की बदौलत बेनामी जायदाद बना ली थी। सरकार अब ऐसी बेनामी जायदाद को अधिकृत करेगी, अब बेनामी जायदाद बनाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है।

'GST- One Nation, One Tax' काफी सालों से लंबित था। पिछली सरकार 2005 में यह टैक्स लाई, पर उसको लागू नहीं कर सकी। उसको लागू करने का श्रेय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को जाता है। आज जीएसटी सफलतापूर्वक चल रहा है। जीएसटी से डेढ़ लाख करोड़ रुपए प्रति महीना कलेक्शन आ रहा है। लोग खुश होकर यह टैक्स दे रहे हैं। आज digital transaction, transparent transaction शुरू हो गया है। आज Ayushman Bharat Scheme के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का health insurance मिला। इस 5 लाख रुपए में दवाई, डॉक्टर, hospitalisation, post-hospitalisation and admission मुफ्त है। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पंजाब में Ayushman Bharat Scheme को लागू करने में एक वर्ष की देरी क्यों की गई? यह ऐसी योजना है, जिसके तहत गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मिल रही हैं। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि बीमारी के बाद हमारी आयु खत्म हो गई, आज उनको इस योजना के माध्यम से आयु मिल रही है। इसके तहत heart-transplant हो रहे हैं, हर तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं। ओबामा की यह योजना थी, जो केवल 10 करोड़ लोगों को मिली थी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। इस योजना से देश के गरीब लोगों को लाभ मिला है।

अब मैं 'उज्ज्वला योजना' की बात करना चाहता हूँ। पंजाब में प्रधान मंत्री जी ने एक अपील की कि जो लोग समृद्ध हैं, वे अपनी सब्सिडी छोड़ दें। यह है इनका कद, यह है इनका स्नेह। जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ कर इन्होंने लोगों को इसके लिए motivate किया कि जो लोग समृद्ध हैं, वे अपनी सब्सिडी छोड़ दें। इसके माध्यम से करोड़ों रुपए आए।

आज पंजाब के हर घर में गैस कनेक्शन है। अब मेरी माताओं-बहनों के फेफड़े चूल्हा जलाने से खराब नहीं होते हैं। उन्हें जीवन मिला है। आज पंजाब में घर-घर बिजली पहुंची है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सड़कों के इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कार्य किए हैं। आज पंजाब में flyovers, over bridges, elevated roads हैं और सड़क भी घर-घर तक पहुंची है। आप जानते हैं कि बिजली और सड़क विकास के द्वार होते हैं, ग्रोथ इंजन होते हैं। अगर इन्हें आज पंजाब के घर-घर तक पहुंचाया है, तो प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया है।

महोदय, आज देश को प्रधान मंत्री मोदी जी ने गौरव दिया है। पाकिस्तान ने उरी में दुस्साहस किया। वह पहले भी दुस्साहस करता रहा था, हम सहते रहे थे, पर वह लौह पुरुष हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ही थे कि जब उरी में कुप्रयास किया गया, तब उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला। 28 सितम्बर, 2016 को जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसमें हमारे राष्ट्र भक्त सैनिकों ने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ जाकर हजारों आतंकवादियों, जो हमारे देश में खून की होली खेलने के लिए तैयार थे, का नरसंहार किया और वे पाकिस्तान की धरती पर उन्हें धूल चटाकर आए। ऐसे ही पुलवामा में दोबारा दुस्साहस किया गया। प्रधान मंत्री जी ने उस समय भी शपथ ली थी। वे सोए नहीं, रात भर जागते रहे। इसके बाद बालाकोट में एअर स्ट्राइक की गई। उसकी सफलता देखिए कि पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। इसके बाद से पाकिस्तान ने दुस्साहस करने की ज़ुर्रत नहीं की। मैं बॉर्डर स्टेट

से आया हूँ, मैं अमृतसर में रहता हूँ। पकिस्तान ने हमारे लौह पुरुष प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सामने घुटने टेके हैं।

मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सवर्ण समुदाय हमेशा कहता था कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हमें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, टैलेंटेड बच्चे मेरिट के ऊपर नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बिना कोई छेड़छाड़ किए दस परसेंट आरक्षण सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया है, जो कि एक स्वर्णिम उपलब्धि है।

मैं एक बात और कहना चाहूँगा। सैकड़ों वर्षों से देशवासियों की राम मंदिर की माँग थी कि अब रामलला का मंदिर बनाना है। इसे लेकर संघर्ष भी हुआ, शहीदी भी हुई। मैं यह कह रहा हूँ कि प्रधान मंत्री जी कथनी और करनी एक है। इन सात वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। जो 70 वर्षों से स्वप्न थे, उन्हें प्रधान मंत्री जी ने साकार किया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तीन तलाक, जो महिला शक्ति का अपमान था...

श्री उपसभापति : माननीय श्वेत मलिक जी, अब समाप्त करें। आपको पार्टी ने जो समय दिया था, वह खत्म हो रहा है। प्लीज़ समाप्त करें।

श्री श्वेत मलिक : सर, मेरे पास अभी वक्त है। अब मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। महोदय, तीन तलाक की कुप्रथा चल रही थी, हमारी महिलाओं-बहनों का शोषण हो रहा था। उस समय भी हमारे दोस्तों ने विरोध किया, पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी विरोध नहीं देखते हैं, वे संकल्प करते हैं। उन्होंने संकल्प पूरा किया और तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म करके महिलाओं को उससे छुटकारा दिलाया।

मुझे याद है कि मैं जापान में काम करता था। मैं छः वर्ष जापान में इंजीनियर रहा, तब मैंने 1987 में बुलेट ट्रेन में सफर किया। मैं सोचता था कि हमारे देश में यह कब आएगी। किसी में इच्छा-शक्ति नहीं थी कि बुलेट ट्रेन आ सकती है। यह इच्छा-शक्ति किसने जगाई? 2014 से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बुलेट ट्रेन लेकर आए, तेजस लेकर आए, गतिमान लेकर आए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय मलिक जी, आप कन्क्लूड करें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ कन्क्लूड करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्वेत मलिक : मैं आज यह रिपीट करूँगा, यह मोदी जी के ऊपर हैः

"मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है।"

मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को नमन करता हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The motion that has been moved and seconded is that an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2022."

There are 99 Amendments to the Motion which may be moved at this stage.Amendments (Nos. 1 to 6) by Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya. Are you moving?

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): Sir, I move:

1. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to check the growing incidents of child abuse in the country."

2. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of the Government to check the ongoing attacks on Students, Journalists and the voice of dissent; and to ensure the safety of the dissenters."

3. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the guidelines for the Government with regard to liberalizing Foreign Direct Investment (FDI) and the portfolio management."

4. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to re-define poverty line without depriving a majority section of people from right to subsidised food as well as other basic necessities."

5. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to pursue independent foreign policy of the country to boost India's image as the leader of 3rd world countries."

6. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about universalization of Integrated Child Development Scheme and increasing the wages of Anganwadi workers."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 7 to 14) by Shri Shaktisinh Gohil.

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, I move:

7. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the kidnapping of Indian Citizen by China and one ruling party member of Parliament has informed through a tweet that China has constructed a road in our territory."

8. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the promise of providing two crore employment every year."

9. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the bringing back of black money and providing fifteen lacs in the accounts of the citizens."

10. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the displacement of families living in vicinity of the Sabarmati Ashram in Gujarat in the name of modernisation and the commitment of not thinking with the simplicity and history of Gandhi Ashram."

11. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the death of citizens due to Corona pandemic and the compensation provided to their families."

12. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the possible direct help to be provided to the small shopkeepers and daily wagers during Corona pandemic."

13. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the formers martyred during the protest of the Black Laws and the compensation to be provided to their families along with the timelines."

14. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the timelines to filfill all the conditions of the accord between the farmers and the Government."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 15 to 20) by Dr. V. Sivadasan, not present. Shrimati Jharna Das Baidya.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I move:

15. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the growing attacks against minority communities, especially Christians and Muslims."

16. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill."

17. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the Bank Nationalisation Act & privatisation of public sector banks."

18. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the killing of 17 innocent civilians in Nagaland."

19. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing intolerance manifesting the violence and spread of communal polarization in the country."

20. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of the Government to increase public investment/expenditure on infrastructure development education, health, etc., and create permanent jobs."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 21 to 24) by Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (WEST BENGAL): Sir, I move:

21. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the price rise particularly the price of petrol and diesel."

22. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Guaranteed MSP for all crops to each farmer of the country and to compensate the families of the Martyrs of the Kisan Movement."

23. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to extend the benefit of MGNREGA to every individual job seeker."

24. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the loss of lakhs of jobs because of the privatization and disinvestment of public sectors and the need for transparent recruitment on merit in Railways."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 25 to 33) by Shri John Brittas; not present. He has not moved. Amendments (Nos. 34 to 41) by Shri Elamaram Kareem.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

34. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the economic crisis through which the nation is going through and the complete failure of the government in dealing with this crisis."

35. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the exponential increase in prices of essential commodities, petroleum products and LPG that has doubled the burden for the common man."

36. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the government in addressing the issues of the farmers by announcing MSP for all crops, ensuring procurement of the crops with remunerative prices and giving compensation to the families of farmers who have died during the farmer's protest."

37. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing intolerance manifesting the violence and spread of communal polarisation in the country and growing attacks against minority communities and dalits."

38. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the killing of 17 innocent civilians in Nagaland by armed forces."

39. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government in increasing public Investment and expenditure on infrastructure development, education, health etc. and providing employment to the youth."

40. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the all-out privatization of national assets including our prestigious PSUs and public sector banks and the reduction in employment opportunities for the youth due to this privatization."

41. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the country wide protests by workers and farmers against the labour codes, anti-farmer legislations and policies of the government."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 42 to 51) by Shri M. Shanmugam.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I move:

42. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the frequent attacks on fishermen from Tamil Nadu by Sri Lankan Navy and the need to take effective measures to find a permanent solution."

43. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rejection of Republic Day Tableau depicting the portraits of freedom fighters from Tamil Nadu proposed by the Government of Tamil Nadu thereby hurting the sentiments and patriotic feelings of the people of Tamil Nadu."

44. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to give exemption from NEET examination for medical college admission to medical

students from Tamil Nadu since the Tamil Nadu Assembly has already passed the relevant NEET Exemption Bill which has been submitted for Presidential assent."

45. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the opposition expressed by most of the States against the proposed changes in the All India Service rules about Central deputation from the States IAS cadre, without obtaining the consent of the State Government."

46. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the high prices of essential commodities despite bumper harvest in the country."

47. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the high prices of petrol, diesel, LPG and petroleum products, thereby hitting the common people apart from high inflationary trend in the economy."

48. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to provide ex-gratia compensation to the kin of all doctors, including private practitioners who lost their lives in the line of duty during the second Covid wave in the country."

49. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to bring a legislation to ban online games which destroy the future career of youngsters."

50. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to restore travel concessions to various categories of railway passengers in the Indian Railways."

51. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to take up urgently the railway work of Thanjavur-Villupuram doubling line in Tiruchi division of Southern Railway."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 52 to 59) by Shri K. Somaprasad.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I move:

52. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the economic crisis through which the nation is going through and the complete failure of the Government in dealing with this crisis."

53. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the exponential increase in prices of essential commodities, petroleum products and LPG that has doubled the burden for the common man."

54. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the government in addressing the issues of the farmers, announcing MSP for all crops, ensuring procurement of the crops with remunerative prices and giving compensation to the families of farmers who have died during the farmer's protest."

55. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing intolerance manifesting the violence and spread of communal polarization in the country and growing attacks against minority communities and dalits."

56. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the killing of 17 Innocent civilians in Nagaland by armed forces."

57. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government in increasing public investment and expenditure on infrastructure development, education, health etc. and its failure in providing employment to the youth."

58. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the all-out privatisation of national assets including our prestigious PSUs and public sector banks and the reduction in employment opportunities for the youth due to this privatisation."

59. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the country wide protests by workers and farmers against the labour codes, anti-farmer legislations and policies of the government."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 60 to 63) by Shri Abdul Wahab; not present. Amendments (Nos. 64 to 69) but Shri M. V. Shreyams Kumar; not present. Amendments (Nos. 70 to 73) by Shri Digvijaya Singh.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I move:

70. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rising inflation, adding misery to the poor."

71. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rising unemployment in the country."

72. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the bringing law to make MSP for Agri-products mandatory."

73. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rise in communal hatred speeches in country."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 74 to 81) by Shrimati Priyanka Chaturvedi.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I move:

74. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about at the rising unemployment in the country and that no concrete steps have been taken to resolve this issue."

75. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about trade with China crossing $125 Billion mark despite the persistent border disputes."

76. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about inefficient utilisation of funds for 'Beti Bachao Beti Padhao"and spending 80% of the funds on advertisement."

77. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the loss of lives and livelihood of farmers during their almost year long protest against the new repealed farm laws."

78. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about increasing cases of harassment and commodification of women in digital space and lack of preventive measures for safety of women in the digital space."

79. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about GST compensation pending for States including Maharashtra for which Rs.6,430 crore is yet to be released by the Government."

80. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about skewed representation of women in parliamentary and executive machinery despite Government's claim on empowerment of women."

81. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention regret on the loss of lives in Nagaland in which six civilians were gunned down."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 82 to 89) by Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

82. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the issue of inflation in the economy which has been at a double-digit high affecting the poor and the middle-class sections."

83. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the issue of inflation in the economy which has been affecting the MSME sector owing to the high input prices."

84. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the fact that despite the Tamil Nadu Legislative Assembly passed the bill to scrap the NEET examination, the same has not been forwarded by the government to the President."

85. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the plight of the Tamil Nadu fishermen facing arrests by the Sri Lankan Navy and authorities."

86. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the States have not been compensated for their due share in the GST."

87. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the grievances of the farmers in the country and the ways to address their problems."

88. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that examinations for several posts under Union Government are still conducted only in Hindi and English disregarding the regional languages."

89. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the issue of unemployment and the measures to address the same in the country."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 90 to 99) by Shri. K. C. Venugopal.

SHRI K.C. VENUGOPAL (Kerala): Sir, I move:

90. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the delayed response of the Central Government to the third wave, despite facing a tragic second wave and Omicron was flagged as a variant of concern in November, 2021, but the government did not impose restrictions on movement or Introduce fresh vaccination polices till late December, 2021-early January, 2022."

91. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about inaccurate COVID-19 data due to increased use of at-home testing kits, as the government has not adequately regulated the sale of these kits, and has not put in any measures to ensure mandatory reporting of results."

92. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about severe shortages of vaccine doses faced by states as late as July, 2021, even after the deadly second wave, leading to 60% decline in the vaccination rate."

93. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about that the expenditure of Rs. 64,180 crores on Health Infrastructure Mission is spread out over six years, which averages out to Rs. 10,700 crores per year and that this increases the healthcare expenditure by a mere 0.05% of GDP."

94. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fact that the Union Government allocated Rs. 6,400 crore in 2020-21 to Ayushman Bharat—Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), but revised estimates of the budget reduced it to Rs. 3100 crore.

95. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fact that India has one of the highest out-of-pocket expenditure rates, almost 62%, making quality healthcare challenging and expensive for the common citizen."

96. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention that around 6 crore beneficiaries of NFSA are left out from the 'One Nation One Ration Card' scheme which leaves significant portion of the population as destitute when migrating to other states in the absence of coverage under the national scheme."

97. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention that 9% of houses have not been sanctioned under PMAY-Rural, and only 72% of sanctioned houses have been completed as of April, 2021."

98. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention that the government's poor prioritisation of the Jal Jeevan Mission is evident in the fact that only 26% of the scheme's allocation for FY 2022 was released by the end of the third quarter."

99. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that because of gaps in bank account linkages, among other reasons, lakhs of eligible farmers have not been receiving either full or partial instalments since the beginning of the PM Kisan Samman Nidhi scheme in 2019."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The motion and the amendments are moved. The two are now open for discussion. Hon. LoP, Shri Mallikarjun Kharge.

The questions were proposed.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : माननीय उपसभापति जी, अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उस तरफ से Proposer और Seconder द्वारा बोला गया। वैसे तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ज्यादा अभिनन्दन की बात होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभिनन्दन से ज्यादा चुनावी भाषण सुना। हम कहीं न कहीं चूक रहे हैं। अब, जब आप कुछ कहते हैं तो हमें भी उसका जवाब देना पड़ता है। इसलिए मैं अपना भाषण इन शब्दों से शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ सरदार भी आए हैं:

"लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दो, अख़बार भी तुम्हारा है।
इस दौर के फरियादी जाएँ तो जाएँ कहाँ,
सरकार भी तुम्हारी है दरबार भी तुम्हारा है।"

...(**व्यवधान**)...

हम देखेंगे कि कितने दिन रहेगी। आप गिनते जाओ, उम्र होती जाती है, आप गिनते जाओ। यह दरबार आपका है और आज आपको हर चीज़ मिली है। इसीलिए आपने यहां पर बहुत सी चीज़ें कहीं। अभी मैं एक माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था, उन्होंने बहुत सी चीज़ें देवालय के बारे में बतायीं, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी भी जानते हैं, जब मैं उस सदन में नेता विरोधी दल के नाते बैठता था, तो उस वक्त एक-दो बार वे बसवण्णा के वचन सुना देते थे। महात्मा बसवेश्वर, जो कर्णाटक में बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। चंद लोग उसको मानते हैं, चंद लोग नहीं मानते हैं, यह अन्य बात है, लेकिन वे समाज सुधार में अपनी बहुत आस्था रखते थे, जिसके लिए उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। उन्होंने एक बात कही है:

"Rich and well to do can afford to build a temple.
How could you expect a poor one like me, to do the same?
I can only assume my legs as the pillars, the whole body as the shrine,
my head as its Kalash (sacred pitcher)"

बसवण्णा ने यह कहा कि 'जिसके पास पैसे हैं, संपत्ति है, वह तो मंदिर बनाता है, देवालय बनाता है, लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने यह कहा, '*I can only assume my legs as the pillars* ' मेरे पैर ही पिलर्स हैं और मेरा देह-हृदय ही देवालय है। '*My head as its Kalash (sacred pitcher)*' जो कलश होता है, उसमें भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा सिर ही कलश है - यह महात्मा बसवेश्वर ने कहा है। यानी सिर्फ पैसों से या पत्थरों की दीवारों से ही देवालय नहीं बनता, उसके लिए अपने हृदय में सच्चे धर्म की भी आस्था होनी चाहिए, उस धर्म पर चलने की आस्था होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए। यह बसवण्णा ने कहा है, इसीलिए मैंने आपके सामने यह रखा है। ...(**व्यवधान**)... जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, वह

एक पॉलिसी डॉक्युमेंट होता है। हम उस अभिभाषण को एक विज़न स्टेटमेंट के तौर पर देखते हैं। यह न ही विज़न है और न ही पॉलिसी डॉक्युमेंट है। आप जो सात साल से करते हुए आए हैं, मैंने एक-एक चीज़ को गिनते हुए बहुत गम्भीरता से पढ़ा है। उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी कही गयीं, जो पहले उन्होंने अपने 8 साल के राष्ट्रपति अभिभाषण में कही हैं, उसी में एक-एक करके कई जगह बदलाव किया गया, कई जगह शब्दों का बदलाव हुआ और कई जगह थोड़ा कार्यक्रम का बदलाव हुआ, वही सब इसमें डाला गया है। वे जो वायदे करते आए थे, जनता के बुनियादी मसलों का हल न करते हुए इसमें अपनी ही बात बार-बार कही।

मैं समझता था कि प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया का यह शायद आखिरी भाषण है। आखिरी है न? इस टर्म में, अगर रिन्यू हुआ तो फिर वह सैकंड होगा, वह बात अलग है। मैंने सोचा था कि वे एक बहुत ही गरीब वर्ग से आते हैं और दलितों के बारे में उनके पास सुधार के लिए बड़ी भावना है तो मैंने समझा कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ नया लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नया मिलने वाला है, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह तो छोड़िये...(**व्यवधान**)...जब आपकी बारी आएगी तब बोलियेगा,...(**व्यवधान**)...बार-बार मुझे मत छेड़ो। मैं भी इसे उतनी ही गम्भीरता से लेता हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल : अगर आप ऐसा करेंगे तो हम किसी को नहीं बोलने देंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है कि उसको कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, किसान और मजदूर की जो बुरी हालत है और एस.सी., एस.टी. पर जो ज्यादती हो रही है, गम्भीर आर्थिक चुनौतियां हैं, उनको भी टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया है।

हमारा लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है क्योंकि ये सच बोलने नहीं देते, सच करने नहीं देते। अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, जो सच बताता है, उसको भी देशद्रोही बोलते हैं, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन अब जब आप अपने विचारों को रखते हैं तो भी उनको नकार देते हैं, लेकिन बार-बार हमें यही याद दिलाते हैं कि 70 सालों में आपने क्या किया। इसे आप कितनी बार बोलेंगे! हर आदमी यही बोलता है कि 70 साल में आपने क्या किया! मैंने भी अनेक बार बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 70 सालों में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज आप जिंदा नहीं रहते। आपने जो कहा, मैं फिर से उसमें नहीं जाता हूं। आज जो प्रजातंत्र और संविधान है, यह रहने की वजह से आप सभी लोग जिंदा हैं और आपको बड़े-बड़े पद मिले हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल : जब प्रधान मंत्री जी बोलेंगे तो हम भी टोका-टाकी करेंगे।

श्री उपसभापति : आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया बीच में आपस में बात न करें। जब आपका मौका आएगा, तब अपनी बात कहें। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप तो हजारों सालों से हमें कुचलते आये हैं।...(**व्यवधान**)...आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...आप हजारों सालों से कुचलते आये हैं, फिर भी हम सहन कर रहे हैं। बार-बार पोलिटिक्स की बात करते हैं। Don't talk politically. ....*(Interruptions)*... I am talking on...*(Interruptions)*... I am giving you the facts. ...*(Interruptions)*... I am giving you the numbers. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : सभी से मेरा आग्रह है कि प्लीज़, आपस में बात न करें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आपको डिफेंड करने के लिए ही बनाया है, आप बनाते रहो।...(**व्यवधान**)...देखिये, आपका काम कम है, प्रचार ज्यादा है और इस प्रचार के लिए आपको भी एक बख्शीश मिलनी चाहिए, क्योंकि आप इतने * को सच बोलते हो और बार-बार * बोलते ही जाते हो।...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : सर, यह * अनपार्लियामेंटरी है।

श्री उपसभापति : हम रिकॉर्ड एग्ज़ामिन कराएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सत्य से दूर...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हम रिकॉर्ड से एग्ज़ामिन कराएंगे, प्लीज़, किसी भी पक्ष ...(**व्यवधान**)...माननीय सदस्यगण, किसी भी पक्ष के द्वारा अगर यह शब्द इस्तेमाल हुआ है तो उसका हम रिकॉर्ड एग्ज़ामिन कराएंगे और नियमतः इसे हम देखेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैं यह कहूंगा...(**व्यवधान**)...ठीक है, वह निकाल दीजिए या उसे असत्य कर दीजिये या यह कि वह सत्य से दूर है। जब विपक्ष आपके कामकाज पर सवाल उठाता है, तो हमेशा आपको धर्म खतरे में दिखता है। हर बार यही कहा जाता है कि धर्म खतरे में है। आप लोग यह कहते हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं, हम डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। हमें ही उल्टा बोलते हैं। जो लोग खुद करते हैं, वही लोग यह बात बार-बार बोलते रहते हैं। दूसरा, मैं

---

* Expunged as ordered by the Chair.

बेरोज़गारी की बात पर आना चाहता हूं। आज हर जगह बेरोज़गारी है। आज युवाओं में संतोष नहीं है, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, बड़े-बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं और सरकारी नौकरियां भी बंद हो रही हैं। सर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में आपने यह कहा था कि मैं हर साल दो करोड़ नौकरियां दूंगा। यह बात सही है। अब तक आपको पन्द्रह करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थीं, लेकिन आज तक कितनी दी हैं? मैंने कल के बजट में देखा है कि पांच साल में 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। उस समय आप वोट लेते वक्त, प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त यही कहते थे कि हर साल दो करोड़ नौकरियां दूंगा। उस समय सारे youngsters ने तालियां बजाईं, क्योंकि उनको लगा कि उनको नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन हुआ यह कि आज दो करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं और unemployment बढ़ रहा है। सर, बिहार और यू.पी. में रेलवे की नौकरियों के लिए लोग रास्ते पर आए हैं। आज मैं यह कहूंगा कि मेरे पास जो हिसाब है, उसके अनुसार भारत सरकार में करीब नौ लाख नौकरियों के पद खाली हैं, रेलवे में 15 परसेंट खाली हैं, डिफेंस में 40 परसेंट खाली हैं, होम में 12 परसेंट खाली हैं और पी.एम.ओ. ऑफिस के बारे में तो मत पूछिए, वहां पर भी खाली हैं-खासकर वहां शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है। सेक्रेटेरिएट में भी जगह नहीं है, वहां पर एक-दो सेक्रेटरी नहीं मिल सकते, डिप्टी सेक्रेटरी नहीं मिलते हैं। देखिए मैं अपनी बात रखूंगा, बाद में आप अपने statistics के साथ बात कीजिए। मैं आपको वेलकम करता हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : उपसभापति महोदय...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अठावले साहब, आप बार-बार मत उठिए। वे आपको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ...**(व्यवधान)**...क्योंकि मैं आपका आदर करता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अठावले जी, आपको बोलने की अनुमति नहीं है। प्लीज़, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: दूसरी बात यह है कि आज आपने पांच साल में 60 लाख नौकरियां देने की बात की है, तो पहले हर साल दो करोड़ नौकरियां देने की बात क्यों की? आपने क्यों युवकों को गुमराह किया? दूसरी चीज़, आज शहर में बेरोज़गारी की दर 9 परसेंट है और ग्रामीण क्षेत्र में 7.2 परसेंट है, औरतों की बेरोज़गारी दर 26 प्रतिशत है, जो पुरुषों के मुकाबले में 8 परसेंट है। यह तीन गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाली एमएसएमई की 60 परसेंट यूनिट्स बंद होने के कगार पर हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां भी सब यूनिट्स जो बंद हुई हैं, उनको

चालू करने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए सिर्फ भाषण में ही ज्यादा कहा गया है, लेकिन actual अनुष्ठान में कुछ भी नहीं है।

इसके बाद जब बेरोजगारी की बात आती है, तो उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट 'मनरेगा' लाई थी। जब हम 'मनरेगा' की योजना लाए, तब मोदी साहब बोलते थे कि खरगे साहब, यह तो आपका जीता - जागता विफलता का स्मारक है। साहब, उसी स्मारक और उसी 'मनरेगा' ने आपके कोविड में काम किया, लाखों लोगों की जान बचाई और देहात में जो लोग, जो माइग्रेंट वर्कर्स पलटकर गए, उनको जो काम मिला, वह 'मनरेगा' के हिसाब से मिला। इसमें उनको आप कितने पैसे दे रहे हैं? आपके हिसाब से मिनिमम वेज जो 235 रुपये है, अगर हम एवरेज 200 रुपये भी पकड़ें, तो कम से कम आपको 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये रखने चाहिए थे, लेकिन आपने इसमें कितने रखे - 73 हज़ार करोड़ रुपये। ...(**व्यवधान**)... आपने तो सौ दिन के लिए नौकरी देने का वायदा किया था और यह भी कहा था कि कोविड में हम 150 दिन तक देंगे, लेकिन दिया कितना - सिर्फ 20 दिन सबको नौकरी मिली है। यही आंकड़े उनके पास हैं और उन्हीं आंकड़ों से मैंने यहां दिया है। सात करोड़ householders जो बेरोजगार हैं, उनको कोविड के दिनों में 150 दिन और कम से कम 100 दिन कानून के तहत नौकरी देने की बात कही गई थी। ...(**व्यवधान**)... लेकिन आज जो पैसा आपने रखा, वह सिर्फ 73 हज़ार करोड़ रुपये है। तो यह 'मनरेगा' की वजह से कुछ बचा और आपकी मान-मर्यादा, सब कुछ यूपीए गवर्नमेंट की स्कीम से बची, आपकी वजह से नहीं।

सर, अब मैं price rise, wholesale price rise के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो महंगाई के बारे में ज्यादा नहीं समझाया गया और बात भी नहीं की गई, उसका जिक्र भी नहीं किया गया। यह 2021 में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 14.23 परसेंट हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 12 साल में उतनी महंगाई नहीं थी। ...(**व्यवधान**)... आज inflation 14.23 परसेंट हो गया है। यह तो आपको मालूम है कि 2020 में कच्चे तेल की कीमतें 25 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल का दाम बढ़ता रहा। जनवरी से नवम्बर, 2021 के बीच पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 30 परसेंट अधिक बढ़ीं। आपने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 275 परसेंट excise duty बढ़ा दी। पिछले सात सालों में केवल excise duty पर आपने जो पैसा कमाया, वह करीब 25 लाख करोड़ रुपये है। फिर भी हर साल, हर वक्त, हर दिन, हर हफ्ते पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ते ही जाते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा। कहां हैं ये अच्छे दिन? रोज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, inflation हो रहा है, दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, pulses के दाम बढ़ रहे हैं और इसमें एलपीजी भी है। 'उज्ज्वला योजना' की चर्चा तो आप हमेशा बहुत करते हैं। मैं इसके बारे में भी पूछना चाहता हूं। हर एक आदमी को एलपीजी की जरूरत है, इसका दाम 117 परसेंट बढ़ गया है।

1.00 P.M.

वर्ष 2014 में सिलेंडर की कीमत 414 रुपये थी और आज, आपके ज़माने में वह बढ़कर 1,000 रुपये तक आ गई है, यही आपके अच्छे दिन हैं! ...(**व्यवधान**)... आप अच्छे दिन अपनी करतूत में

दिखा रहे हैं, अनुष्ठान में दिखा रहे हैं। आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, यह इससे मालूम होता है। इसी के साथ-साथ अन्य चीज़ों की जो कीमतें बढ़ गई हैं, जो दाम बढ़ गए हैं, वे 81 परसेंट तक पहुंच गए हैं। दालों के दामों में 60 परसेंट, सब्जियों के दामों में 50 से 84 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। सभी जरूरी सामानों के, जितनी भी essential commodities हैं, उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं। मेरे पास इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, इसे मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सकता हूं। अनाज की कीमतें 2014 के मुकाबले में 52 परसेंट बढ़ी हैं। तुअर की कीमत क्या है, इसकी कीमत 39 परसेंट बढ़ी है। चना दाल 60 परसेंट बढ़ी है, मसूर की दाल 39 परसेंट बढ़ी है और मस्टर्ड ऑयल की कीमत 41 परसेंट बढ़ी है, वनस्पति की कीमत 59 परसेंट बढ़ी है। अगर मैं इन सारी चीज़ों की लिस्ट पढ़ता जाऊँ, तो सभी चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। मैं इसको दे दूंगा कि कितना आपने बढ़ाया और फिर भी अच्छे दिन आए! एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ आपने जो कहा था, उसको भी आप नहीं निभा रहे हैं, तो फिर ये अच्छे दिन आए कहाँ और अच्छे दिन किनके लिए आए! सिर्फ यहां तालियां बजाने से, हमें हूट आउट करने से मसला हल नहीं होता है। यह तो आपकी करतूत है, आपकी देन है। यह ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। आपके बजट में है, आपके भाषण में है। यह मैं आपको बता रहा था।

महोदय, हंगर इंडेक्स में हम कहां हैं? सर, 116 देशों में भारत 101 नम्बर पर है।...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : यह गलत है। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अगर यह गलत है, तो आप मुझे भेज दो, मैं करेक्ट करके आपको भेज देता हूं। आपने बताया कि आप 80 करोड़ जनता को फ्री फूड दे रहे हैं और मार्च तक उसको extend करेंगे। मार्च तक पांच राज्यों में इलेक्शन्स हैं, इसीलिए यह मार्च तक गया, नहीं तो यह इसी महीने में खत्म हो रहा था, लेकिन आपने इसे मार्च तक extend कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को कौन लाया था? श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा गरीबों का पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया और इसके माध्यम से हर गरीब की फैमिली को कम से कम 35-35 किलो अनाज देने का प्रावधान उनके द्वारा किया गया। ...**(व्यवधान)**...तब से हम इस काम को कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : क्या वे प्रधान मंत्री थीं? ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : देखिए, मैं सोनिया गांधी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि वे चेयरपर्सन थीं। ...**(व्यवधान)**....

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप लोग आपस में बात मत करिए। माननीय एलओपी, आप चेयर को एड्रेस करें। कृपया आप आपस में बात न करें, माननीय एलओपी।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : वे चेयरपर्सन थीं और बहुत से सलाहकार उनके साथ थे, जो आईएएस और आईपीएस थे। एक कार्यक्रम बना, जिसको डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लागू किया। हम भी उसमें थे, हमने उसको इम्प्लिमेंट किया। हम कोई चीज़ इम्प्लिमेंट करते हैं, तो आपको क्यों दर्द होता है? कभी नेहरू जी का नाम लेते हैं, तो दर्द होता है, सोनिया गांधी जी का नाम लेते हैं, तो दर्द होता है, राजीव गांधी जी का नाम लेते हैं, तो दर्द होता है! अब आजकल राहुल जी का नाम लिया, तो भी आपको दर्द होता है। ..(**व्यवधान**).. पेट में कितना ..(**व्यवधान**)..

श्री प्रहलाद जोशी : राहुल गांधी..(**व्यवधान**)..सोनिया गांधी..(**व्यवधान**)..राजीव गांधी ..(**व्यवधान**)..

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यहाँ तक कि वाजपेयी का नाम भी आजकल नहीं चल रहा है। ..(**व्यवधान**)..वाजपेयी का नाम भी नहीं चलता, आडवाणी का नाम भी नहीं चलता। ..(**व्यवधान**)..

श्री प्रहलाद जोशी : सुभाष चंद्र बोस का नाम..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : प्लीज़।..(**व्यवधान**)..

श्री प्रहलाद जोशी : सुभाष चंद्र बोस..(**व्यवधान**)..

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, सुभाष चंद्र बोस तो हमारे लीडर थे, उनके नहीं थे। ..(**व्यवधान**)..छोड़िए।

सर, मैं एक और दूसरी बात आपके सामने रखूंगा और वह भी बड़ी गंभीरता की बात है, यह सभी को मिलकर सुलझाने की बात है। यह जो economic inequality आई है, यह unprecedented है और मैं इस पर आंकड़ों के साथ कहूंगा कि इस देश में 1 परसेंट लोगों के पास 22 परसेंट इन्कम है, 9 परसेंट लोगों के पास 35 परसेंट इन्कम है, मिडिल क्लास के 40 परसेंट लोगों के पास 30 परसेंट है, बॉटम के जितने भी 50 परसेंट दलित, शोषित और वंचित लोग हैं, उनके पास सिर्फ 13 परसेंट है। यह जो रेश्यो है, इसमें कमी करने की कोई कोशिश नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि इसकी कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में हुई थी। आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस वक्त यह 50 परसेंट ही 10 परसेंट लोगों के पास था, लेकिन अब जो है, अब वही 57 परसेंट हो गया है। योजनाएं बनाई गई थीं, प्लानिंग कमीशन की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई गई थीं, प्लानिंग कमीशन द्वारा गरीबी कम करने के लिए, देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े डैम्स बनाए गए, इरिगेशन के डैम्स बनाए गए। सर, चंद एरियाज़ में जो IITs बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं,

एम्स बने हैं, अभी उनकी बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन इसकी बुनियाद किसने डाली, देश किसने बनाया, आप इसके बारे में तो सोचिए! पहली बात तो यह है कि घर बनते-बनते बनता है, एक दिन में घर नहीं बनता है। हमने बुनियाद डाली, सारी चीज़ें लाए और आप उसमें झंडा लगाने का काम कर रहे हैं, फलक पर चढ़ाने का काम कर रहे हैं।

दूसरी एक और बात चीन की है। महोदय, जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी 2013 में चुनावी उम्मीदवार थे, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरी तैयारी चल रही थी, सोशल मीडिया पर, इधर-उधर एडवरटाइज़मेंट हो रहा था, as a Chief Minister उन्होंने क्या काम किया था आदि-आदि, तब सभी लोग गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल ही बोलते रहते थे। अगर मैं गुजरात मॉडल के लिए बोलूंगा, तो नक़वी साहब को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये बोल देंगे। ..(**व्यवधान**)..सर, 2013 में आपने क्या बोला था, मैं उसको क्वोट कर रहा हूं। आपने कहा था, जब बॉर्डर पर चीन के द्वारा गड़बड़ी हो रही थी, तब आपने उस पर यह कहा था, 'सरकार को लाल आँख कर चीन को समझाना चाहिए था।', लेकिन जब चीन हमारी जमीन छीन रहा है, वहाँ घर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तब साहब, आपकी आँखें क्यों नहीं लाल हो रहीं? आपने हमें नसीहत दी, हमें कहा कि चीन को लाल आँखें निकालकर बताना चाहिए, वह कहे कि हाँ, आँख है, लेकिन अब तो आप चीन के बारे में कुछ बात ही नहीं करते हैं। आप मौन धारण किए हुए हैं - मौन धारण। केदारनाथ की गुफा में जाकर जैसा मौन धारण करते हैं, वैसा मौन धारण आपने किया है। लेकिन यह हमारी territory है, जो disputed territory है। मैं यह नहीं बोलता, disputed territory में आज ये जो मकान बन रहे हैं या मैं आपको ...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी साहब, आपकी पार्टी के द्वारा जो आपका तय समय था, वह खत्म हो रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अपनी पार्टी का समय मैं तय करता हूँ।

श्री उपसभापति : आप ही ने जो समय तय किया है, आपके द्वारा तय समय खत्म हो रहा है। आप बोलिए प्लीज़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सदस्यों के समय में कटौती होगी, मैं यह सिर्फ आपकी सूचना के लिए कह रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं देख लूँगा।

सर, यह है चीन, यह है घर, जहाँ यह बन गया है, यह है सड़क। फिर आपने इसके बारे में अब तक चुप्पी क्यों साधी है, आप क्यों इसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... यह आपका चुप बैठना, ...(**व्यवधान**)... इसके बारे में explain करना पड़ेगा, ...(**व्यवधान**)... इसके बारे में कहना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... हमारे सैकड़ों सैनिक वहाँ बॉर्डर पर हैं। ...(**व्यवधान**)... बहुत से सैनिक वहां पर शहीद हो गए। इसीलिए आज वे एक तरफ हैं।

दूसरी चीज़, आपको चीन से इतना प्यार है। 2013 में import ...*(Interruptions)*... सर, मैं आपको बताता हूँ, 2013 में import 3 लाख, 8 हजार करोड़ रुपए का था, जबकि 2021 में 7 लाख, 20 हजार करोड़ रुपए का import हो रहा है। इसका मतलब यह ज्यादा हुआ या कम हुआ! उस ज़माने में 3.08 लाख करोड़, 2003 में, आज आप 7 लाख, 20 हजार करोड़ का import कर रहे हैं। हमारा trade deficit कितना है! यह 2013 में 2 लाख, 70 हजार करोड़ रुपए था, आज यह बढ़ कर 5 लाख, 25 हजार करोड़ रुपए हो गया है! आपके चीन के साथ झूले में बैठने के कारण जो हुआ है, यह उसकी देन है। उसने आपका हृदय जीत लिया है, आपने कहा कि झूले में बैठ कर हम एक जगह बात कर रहे हैं, तो इसको दे दो, इससे हम पूरा import वहाँ से कर रहे हैं, जबकि आपका export कम है। इसके बावजूद आप वहाँ जो भेजते हैं, उससे चार गुणा ज्यादा हमारा import है। यह एक तरफा है। यह जो हमेशा आत्मनिर्भरता की बात होती है, मैं इसे आत्मनिर्भरता बोलूँ या चीन पर निर्भरता बोलूँ!

आर्टिकल 370 खत्म करके अमृतसर से आए हुए सांसद जोर-जोर से बोले कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। साहब, 370 जाने के बाद 500 आतंकी घटनाएँ घटीं। यह 500 increase हुईं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं, आपको तो अनुभव है, हमारे पड़ोसी देशों से जितना हो सके, उतना मिल-जुल कर चलने की कोशिश होनी चाहिए। जहाँ दुश्मन हमारे लिए बहुत मुसीबत बनता है, तो उसको खत्म करो ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRALHAD JOSHI: Are you going to bring back Article 370? ...*(Interruptions)*... Please clarify your stand. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... मेरा आप सबसे अनुरोध है, please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आत्मनिर्भरता की बात के ऊपर मैंने पहले ही यह कहा कि ये जो IITs हैं, AIIMS है, Polytechnic है, ITI है, ऐसी-ऐसी चीजें बना कर उस वक्त भी skill development को प्रोत्साहन मिला। लेकिन आज 'Make in India' की घोषणा करने के बावजूद भी भारत यशस्वी क्यों नहीं हो रहा है? आपने हमारी manufacturing growth को भी सालाना 14% तक लाने की बात कही थी, लेकिन यह माइनस 7.2% हो गई है। इस तरह हर फील्ड में, चाहे economic growth की फील्ड हो, Make in India की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो या चाइना की बात हो, जो बातें भी आपने कही थीं, आज वे सब एक के बाद एक फेल हो रही हैं।

महोदय, देश के लिए और देश के गरीबों के लिए disinvestment एक बड़ी चीज़ है। आज हम सब चीज़ों में privatisation करते जा रहे हैं। जो फायदे की कंपनीज़ हैं, कारखाने हैं, उन सबको भी हम privatise कर रहे हैं। Air India तो बातचीत करके loss में चली गई, लेकिन LIC तो फायदे की थी, मुनाफे की थी, तो फिर LIC में disinvestment क्यों कर रहे हैं? इस तरह आप एक को नहीं, हरेक को, चाहे Airports हों, public sector के दूसरे units हों, सबको आप privatise कर रहे हैं। अब

तो आप बैंकों में भी हाथ डाल रहे हैं। जिनको आपकी तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, वे सब आज खत्म हो रहे हैं। जब public sector खत्म होता है, तो नौकरियां भी खत्म होती हैं और रिज़र्वेशन भी खत्म होता है। गरीबों को, OBCs को, SC/STs को या economically weaker section को जो फायदा मिलता है, वह पूरा खत्म हो जाता है। बाकी लोगों को आप नौकरियां देंगे, तो contract basis पर, daily wages पर देंगे, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है। वे कहां जाएंगे? आप assured jobs को एक के बाद एक करके निकाल रहे हैं, गरीबों को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप कहना चाहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। PSUs में 2013 में 13,50,000 लोग काम करते थे, जो regular employees थे, 2020 में उनकी संख्या घट कर 9,00,000 हो गई। Contractual labours की संख्या 3,00,000 से बढ़ कर 5,00,000 हो गई। इस तरह हर सेक्टर में आप कमज़ोर हो रहे हैं। जिन चीज़ों से गरीबों को फायदा होता है, वैसी चीज़ों को आप एक-एक करके निकाल रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

अब मैं किसानों पर आता हूं। किसानों की आमदनी को तो आपने दोगुना करने की बात कही है। आपने कही है या नहीं कही? अगर आप कहेंगे कि मैंने नहीं कही, तब तो मैं चुप बैठ जाऊँगा। आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही, लेकिन आप दोगुनी करने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में President's speech में कहीं मेंशन भी नहीं किया गया, उनके बारे में वे कुछ बोले ही नहीं। आमदनी को दोगुनी करने की बात तो पीछे ही रह गई। उसके बाद बड़े-बड़े उद्योगपति उनसे फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन शुक्र है कि किसान एक साल से भी ऊपर वहां पर धरने पर बैठे।...(**व्यवधान**)... जी हां, 14 महीनों तक वे धरने पर बैठे रहे और 700 लोगों ने अपनी जान दे दी। अगर ये तीनों काले कानून आप पहले ही वापस ले लेते, तो ये 700 लोग नहीं मरते, ये बच जाते। आप अपनी हठधर्मी से यह सोचते हैं कि हम जो करते हैं, वही अच्छा है, हमने जो किया, वही अच्छा है। अगर आप यही करते रहेंगे और अपनी बात पर अड़े रहेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चंद बातें दूसरों की भी सुना कीजिए।

आपकी सारी बातें ठीक नहीं हो सकतीं या मेरी भी सारी बातें ठीक नहीं हो सकतीं, यह आप भी मानेंगे। लेकिन जो बहुत नुकसानदायक मामला है, जिसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है - वह एमएसपी का मुद्दा है, आमदनी बढ़ाने का मुद्दा है। ये सारी चीज़ें आपको ठीक करनी चाहिए थीं, लेकिन देरी करने की वजह से आज सात सौ लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए कोई कंपन्सेशन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। इसके अलावा आपने उन्हें क्या-क्या शब्द कहे - बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी और मवाली कहा तथा कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा। इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री के बेटे ने किसानों के काफिले में पीछे से जीप की टक्कर मारकर लखीमपुर खीरी में चार किसानों को खत्म कर दिया। इस बारे में आपको सब मालूम है, लेकिन ऐसी चीज़ें इसमें क्यों नहीं आईं? आप उस मामले में क्या करने वाले हैं, इस बारे में इस स्पीच में कुछ नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो लोग आज आपके साथ बैठते हैं, आप सबसे पहले ऐसे गृह राज्य मंत्री को बाहर निकालिए, क्योंकि इस मामले की इंक्वायरी हो रही है और वे उसे प्रभावित करते हैं। जब इंक्वायरी होती है तो influence जरूर पड़ता है और इसीलिए ऐसे लोगों को

आपको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। उनके भाषण भी ऐसे ही थे - उन्होंने किसानों को धमकी दी और कहा - सुधर जाओ, नहीं तो दो मिनट में हम सुधार देंगे। यह उनका कहना था, आपने भी पढ़ा होगा। आप हमेशा क्विक एक्शन लेने वाले हो, तो फिर इसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको उसे क्विक ड्रॉप करना था, लेकिन आपने नहीं किया, उसका कारण यह है, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आ रहा है लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं।

पीएम किसान योजना आपने बनाई, इसमें दो हजार रुपये देने का प्रावधान है। फसल बीमा योजना में 18 हजार करोड़ रुपये का फायदा इंश्योरेंस कम्पनियों को हुआ, इसका फायदा किसानों को नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा उन्हें फायदा हुआ। वह स्कीम अभी भी चल रही है और उससे कंपनियां लाभ उठा रही हैं तथा बीज, खाद, डीज़ल, पानी और इलेक्ट्रिसिटी आदि के दाम किसानों के लिए बढ़ ही रहे हैं। दूसरी तरफ आप अमीरों को मदद कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि ये सारे आपके दोस्त हैं, लेकिन उनमें बहुत से लोग आपके दोस्त हैं, जो पहले से आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

दूसरा मुद्दा दलितों का है। दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। जब दलितों की बात आती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की बात आती है, बैकवर्ड लोगों की बात आती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि तुमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप क्या कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको आपके ज़माने के आंकड़े देता हूं। अगर हमारे ज़माने में गलती हो गई, तो आपने हमें बताया, हमने जो करना था, वह कर दिया, लेकिन 2015 से लेकर 2020 के दौरान शेड्यूल्ड कास्ट्स के खिलाफ अपराधों में 30 परसेंट और एसटीज़ के खिलाफ 26 परसेंट की बढ़ोतरी हुई। ...(**व्यवधान**).. उनको हरिजन नहीं बोलते हैं, एससी, एसटी बोलते हैं। कहां कौन सा शब्द प्रयोग करना है, उन्हें वह भी मालूम नहीं है। हरिजन कौन है, ये एससी, एसटी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं। ...(**व्यवधान**).. ये आंकड़े 30 परसेंट और 26 परसेंट है। उसके बाद 2018 से शेड्यूल्ड कास्ट्स का स्कॉलरशिप का मामला है।

इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम 6,000 करोड़ रुपये थी, वह घट कर 1,300 करोड़ हो गयी है। ये आपके ही आंकड़े हैं। इसे मैंने आपके पास से ही लिया है। इतनी मेहरबानी आपने scheduled castes के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर की है। सबसे बुरी हालत अब यह हो रही है कि बहुत सी जगहों पर Christian community पर, चर्चों में 2021 से लेकर अब तक 500 हमले हुए हैं। कहीं कन्वर्ज़न के नाम पर हमला करना, कहीं आप धर्मांतरण कर रहे हैं, यह कह कर उनके ऊपर हमला करना- यह सब हो रहा है। ये जो संस्थाएँ हैं, यहाँ तक कि मदर टेरेसा की संस्था, जिसका दुनिया-भर में नाम है, वहाँ पर भी हरैसमेंट चल रही है। उसी ढंग से कर्णाटक में एंटी कन्वर्ज़न बिल लाकर वहाँ पर भी क्रिश्चियंस को तंग किया जा रहा है। आप किस-किस को तंग करना चाहते हैं? क्या सभी लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं? माइनॉरिटीज़ को भेजना चाहते हैं? क्रिश्चियंस को भी भेजना चाहते हैं? दलितों को तंग और तबाह कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और आप ऊपर से बोलते हैं - अच्छे दिन आयेंगे! 'सबका साथ, सबका विकास' और क्या है - सबका प्रयास? ...(**व्यवधान**)... 'सबका विश्वास और सबका प्रयास', लेकिन यहाँ तो सबकी बरबादी हो रही है!

...(**व्यवधान**)... चर्च तोड़े जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... चर्च के बारे में सभी ने मौन धारण किया हुआ है। किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वह disciplined समाज है। वे अच्छा काम करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, health care का काम करते हैं। यहाँ बहुत से लाभार्थी हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं। अंग्रेज़ी स्कूल में पहले प्रवेश पाने की होड़ लगा देते हैं। ...(**व्यवधान**)... ऐसे लोगों द्वारा उसी संस्था में जाकर, चर्च को तोड़ना ...(**व्यवधान**)... चर्च को नुकसान पहुँचाना ...(**व्यवधान**)... वह भी यीशू, Christ के जन्म दिन पर, 25 दिसम्बर, 26 दिसम्बर, 31 दिसम्बर को ऐसी चीज़ें इस देश में हुईं, इनकी मैं निंदा करता हूँ। आज क्रिश्चियन समाज को, जो एक तरह से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है और गलत इलज़ामात लगाकर आज उनको जो ऐसा कह रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। आप उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनकी समस्याओं को सुलझाइए, लेकिन अगर ऐसे अपने चेले-चपाटों को भेजते रहेंगे और वे बरबाद करके वापस आयेंगे, तो इससे देश का कोई हित नहीं होता। देश के लिए यह ठीक नहीं है।

आपने 'नमामि गंगे' पर तो बहुत पैसे भी खर्च किये, लेकिन गंगा अभी भी मैली है। आपने गंगा में डुबकी भी लगायी, लेकिन आपका सिर पूरा दिख रहा था। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। जिस जगह मुझे लगानी होती है, मैं लगाता हूँ। मैं आपको पूछ कर नहीं लगाता या टीवी पर दिखाने के लिए नहीं लगाता कि लोग मुझे देखें, इसलिए ऐसा नहीं करता। मुझे जो कुछ करना होता है, वह मैं अपने आत्मविश्वास से करता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि मेरे विचार क्या हैं। ...(**व्यवधान**)... आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर यह कहा, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने तो एजुकेशन के लिए Right to Education लाने का काम किया था। The Congress Party ensured that education is recognized as a fundamental right of every Indian. हमने तो इसको fundamental right बना कर एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ मान्यता दी, लेकिन आप उसको नयी दिशा में लेकर जा रहे हैं। RSS के सिलेबस तैयार हो रहे हैं। वे सब एक के बाद एक आ रहे हैं। उसके बारे में आप ज़रा ध्यान रखिए। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, कोविड के मामले में बहुत क्रेडिट लिया गया और प्रारम्भिक भाषण में भी कोविड के बारे में तीन-चार पैरा में बताया गया। आपने भी बार-बार कोविड के बारे में कहा। ठीक है, लेकिन जब कोविड की दूसरी लहर आयी, तब तो आप फेल हो गये। कोविड की दूसरी लहर में जो करना था, उसमें precaution नहीं लेने की वजह से आप बहुत से पूरे ...(**व्यवधान**)... अगर आप इसका statistics या real data निकालें, तो 50 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो गयी हैं। ...(**व्यवधान**)... रास्ते पर और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, हर जगह लाशें, लाशें जलाने की जगह नहीं थी। गंगा नदी में बहुत सी लाशें तैर रही थीं। ...(**व्यवधान**)... आपने टीकाकरण की जो बात की, इसमें तो आप अभी 50 परसेंट पर हैं। कल मैंने Economic Survey देखा। उसमें आपने 49 परसेंट के करीब बताया है। जब आपके Economic Survey में वह फिगर है, तो यह फिगर कहाँ से आ गयी कि हमने 70 परसेंट तक दिया, फलानां दिया? यह आप पहले देख लीजिए, देख कर इसे दुरुस्त कर लीजिए और दुरुस्त करके फिर सदन के सामने आइए, यह मेरा कहना है।

कोविड के मामले में कोर्ट ने हरेक को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने को कहा है। तो आप कितना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, अभी कितने लोगों को दे रहे हैं, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। हमारी पार्टी ने तो मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये देने की माँग की थी। मैंने खुद आपसे मिल कर अपना लैटर दिया, सोनिया गांधी जी का लैटर दिया, मनमोहन सिंह जी का लैटर दिया, हमने जो-जो लैटर लिखे थे - राहुल गांधी जी ने भी, सभी ने, मैंने आपसे मिल कर आपके घर में आपको वे दे दिये थे, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ? क्या मेरा लैटर अपवित्र था, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं हुआ।

मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। Prime Minister CARES Fund की बात है। आप तो हर पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। Prime Minister CARES Fund में हमारे भी पैसे जुड़े हैं, जवानों के पैसे जुड़े हैं, NGOs के पैसे जुड़े हैं, दूसरे लोगों ने भी उसमें पैसे डाले हैं, फैक्टरीज़ वालों ने, बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने डाले हैं। उसका हिसाब दीजिए, उसे क्यों छिपा रहे हैं? उसमें क्या है? आप तो कोई बात छिपाना नहीं चाहते, आपकी तो transparency है। जब आपकी transparency है, तो इस पर ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? यह CAG report में क्यों नहीं आना चाहिए? ये सारी चीजें हैं। आपका ट्रस्ट तो एक अलग ही प्रकार का हो गया, क्योंकि उस पर मैंने अलग कानून बना लिया, इसलिए किसी के सामने हिसाब देने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है - जो कुछ भी है, मेरे पास है, मैं जिसको दूँगा, उसी को दूँगा, वह मेरा है। यह आपका नहीं है साहब, यह देश की जनता का है, देश के लोगों का है। उन्होंने विश्वास करके आपको दिया, उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा, मैं इसकी डिमांड करता हूँ। उपसभापति जी, ये उसका हिसाब दें कि किन-किन चीज़ों के लिए खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किस बात पर खर्च किया, कितना जमा हुआ। ...(**व्यवधान**)... कितना जमा हुआ, वह भी हमें बता दीजिए।

महोदय, उसके बाद labour welfare की बात है। यह क्या है? सर, ये labour से जुड़े 4 कानून बहुत मुश्किल हैं। इनको आप वापस लीजिए, जैसे किसानों से जुड़े 3 कानून वापस लिए। यह उसी तरह से labour के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि कोई भी किसी को भी डिसमिस कर देता है। ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। यूनियन की बात कोई नहीं सुनता है, इसीलिए अगर लेबर की बात को मानना है, तो आपको labour welfare से संबंधित इन चार कानूनों को भी वापस लेना चाहिए।

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी साहब, चूँकि समय आप खुद तय करते हैं, इसलिए मैं आपकी सूचना के लिए आपको कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के 5 speakers और हैं, जिन्हें आपने समय दिया है। आप अब तक लगभग एक घंटे का समय ले चुके हैं, इसलिए अब आप बाकी स्पीकर्स के समय के बारे में सोचिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद यह सदन सुनियोजित रूप से चल रहा है। चूँकि विषय को रखना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा।

श्री उपसभापति : मैं आपके द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही आपको याद दिला रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा।

श्री उपसभापति : मेरा समय नहीं, बल्कि आपकी पार्टी का समय, जो आपने निर्धारित किया है, वही मैंने आपको बताया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, इसके लिए समय को extend करना आपके हाथ में है।

श्री उपसभापति : यह मेरे हाथ में नहीं है। जो बीएसी ने तय किया है, उसी के अनुसार हम कर सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : ठीक है, सर। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। GDP growth और fiscal policies के बारे में बजट पर डिस्कशन के समय बताएँगे। जब demonetization की बात आई थी, तब डा. मनमोहन सिंह जी ने कुछ कहा, तो उस समय उनका मज़ाक उड़ाया गया। उस वक्त उन्होंने यह कहा कि यह तो organized loot है, legalized plunder है, monumental mismanagement है। यह नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी। "Note-ban is an undemocratic move like an unguided missile fired unilaterally...", - यह अमृत्य सेन की बात है। उन्होंने यह बात कही। आज GST और demonetization को लाने के कारण ये सारी चीज़ें हो गई हैं। चूँकि आपने मुझे समय के संबंध में याद दिलाया, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा।

श्री उपसभापति : मैंने याद नहीं दिलाया, आपने घंटे भर का समय ले लिया, यह आपका समय है। यह समय आपका है और इसको आपने allocate किया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं आखिरी बात बोल कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप हर जगह अपने political opponents के खिलाफ ED या CBI का इस्तेमाल करते हैं और IT की raid डलवाते हैं। आप यह politically मत कीजिए। अगर economical offence है, तो उसके तहत कार्रवाई कीजिए। कोई आपकी पार्टी से इधर आ गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और अगर कोई इस पार्टी से उधर गया, तो उसका सब छुप जाता है। यह क्या है? कोई एमपी defect हुआ, तो उसको ticket भी मिलता है और ED के case भी बंद होते हैं। अगर कोई एमएलए आपके पास आता

है, तो उसकी मदद से वहाँ हुकूमत बनती है। यह गोवा, कर्णाटक, गुजरात, मणिपुर तथा और जगहों पर होता है। अगर ऐसा होता है, तो उसके खिलाफ जो file रहती है, उसको आप बंद कर देते हैं। आप 'खुल जा सिम-सिम' बोल कर सबकी फाइल खोलिए।

सर, हमने भी बड़े-बड़े काम किए थे और आपने जो काम किए हैं, उनका जिक्र इसमें है। मुझे इस संबंध में कुछ बोलना था, लेकिन आपने समय के संदर्भ में ठीक कहा कि दूसरों को भी समय मिलना चाहिए।

श्री उपसभापति : मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि चूँकि पार्टी का समय आप तय करते हैं और आपने अपने लिए 30 मिनट का समय तय किया है - आप पूरा समय लें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बीएसी में जो समय तय करते हैं, उसी के अनुसार हमें चलना है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं अपने Chief Whip से मिलूँगा और फिर आपका दिल जीतने का कोशिश करूँगा। अब मैं यह कहूँगा :

"जो दे रहे हैं तुम्हें फल पके पकाए हुए,
ये पेड़ तुमको मिले हैं लगे लगाए हुए।"

ये IIT, IIM, development, education - ये सब हमारे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। ये तो लगे-लगाए पेड़ हैं। यह सब हमने किया है।...(**व्यवधान**)...ये चीज़ें हमने की हैं, हमने लगाई हैं, इसका फल सबको मिल रहा है। आप क्रेडिट लीजिए, आप नए-नए बोर्ड लगाइए, नए-नए नाम बदलिए, क्योंकि नेहरू जी के नाम से तो आपको नफरत है। आप उनके संस्थान का नाम बदलते ही रहते हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, आखिर में एक बात कहकर, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। यह बात मेरी है।

"अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है,
जो गरीबों से पसीने की कमाई माँगे,
जुबाँ तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे,
मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब तो दे।"

महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने बहुत समय दिया। मैं आपके संयम की प्रशंसा करता हूँ। अगर मेरी पार्टी के पास 10-15 मिनट हैं, तो प्लीज़ उन्हें दे दीजिए, जय हिन्द!

श्री उपसभापति : आपने अपनी पार्टी के लगभग एक घंटा छः मिनट लिए हैं। यह मैं रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ। अब मैं माननीय सदस्य सुखेन्दु शेखर राय जी को आमंत्रित करता हूँ। ...(**व्यवधान**)... हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रो. राम गोपाल यादव जी कल हाउस में नहीं होंगे, वे बाहर जाना चाहते हैं,

इसलिए वे बोलना चाहते हैं। अगर सदन की अनुमति है, तो आपके बाद मैं राम गोपाल यादव जी को बोलने का अवसर दूँगा।

श्री सुखेन्दु शेखर राय (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, चूँकि मेरे दो स्पीकर्स हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। राम गोपाल यादव जी आसानी से बोल पाएंगे।

श्री उपसभापति : आप बोल लीजिए। आपके बाद मैं माननीय सदस्य राम गोपाल यादव जी को बुलाऊँगा।

श्री सुखेन्दु शेखर राय : सर, पहले सबको जाने दीजिए, फिर मैं बोलूँगा। मैं एक मिनट लेता हूँ, सभी को जाने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : कृपया आप सभी बैठ जाइए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, upon hearing the Address of the President of India, the immediate reaction that crept in my mind was that it was a conceited, self-promoting charlatan. It has reminded me of old *gazal* of Sahir Ludhianvi. The *gazal* was composed by Ravi और उसे महेन्द्र कपूर जी ने गाया था। वह 1973 की फिल्म थी और उसका नाम 'धुंध' था। इस फिल्म में जो गाना रवि जी ने compose किया था और साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था, मैं उसकी चार लाइनें पढ़ना चाहता हूँ।

"ये राह कहाँ से है ये राह कहाँ तक है,
ये राज़ कोई राही समझा है न जाना है,
संसार की हर शय का इतना ही फसाना है,
इक धुंध से आना है, इक धुंध में जाना है।"

Sir, to me, the entire speech of the hon. President is covered with dhund or mist. Now, let me unfold the misty scenario projected in the President's Address.

Firstly, in Paragraph 14, the hon. President has quoted from Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar which said and I quote: "My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity...." What is the performance of this Government in so far as the equality is concerned? I am putting this question to me, Sir, and pat comes the reply that one should go through OXFAM Report published in January, this year which *inter*

alia says 'that the income of 84 per cent households in the country declined in 2021, but at the same time, the number of Indian billionaires grew from 102 to 142.'

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

The OXFAM Report, released ahead of the World Economic Forum's Davos Agenda, also found that the country's healthcare Budget saw a 10 per cent decline from the Revised Estimates of 2020-21. There was a 6 per cent cut in allocation for education, the OXFAM Report says, while the budgetary allocations for the social security schemes declined from 1.5 per cent of the total Union Budget to 0.6 per cent. The India supplement of the global report also says that in 2021, the collective wealth of India's hundred richest people hit a record high of Rs. 57.3 lakh crore or US$ 775 billion.
In the same year, the share of the bottom 50 per cent of the population in the national wealth was a mere 6 per cent. Indians, meanwhile, are estimated to have fallen into extreme poverty in 2020, nearly half of the global 'new poor', according to the United Nations. The report says, "This surge comes at a time when India's unemployment rate was as high as 15 per cent in urban areas and the healthcare system was on the brink of collapse." According to Oxfam India CEO and I quote, "Stark reality of inequality contributing to the death of at least 21,000 people each day, or one person every four seconds." Sir, this report also indicates that a particular company which ranked 24th globally and second in India, witnesses its net worth multiply by eight times in a span of one year, from 8.9 billion US Dollar in 2020 to 50.5 billion US Dollar in 2021. And there is another company and its worth doubled in 2021 to US Dollar 85.5 billion from 36.8 billion US Dollar in 2020. So this is the economic disparity that has occurred in the last financial year in India. Sir, the Oxfam report also points out to the increase in indirect taxes as a share of the Union Government revenue last four years, while the proportion of corporate tax in the same year was declining. The additional tax imposed on fuel has risen 33 per cent in the first six months of 2020-21 as compared to the last year, 79 per cent more than the pre-Covid levels. At the same time, the wealth tax for the super- rich was abolished in 2016. Lowering of corporate taxes from 30 per cent to 22 per cent to attract investment last year resulted in a loss of Rs.1.5 lakh crore, which contributed to the increase in India's fiscal deficit, the report says and there was no increase in private investment in spite of so many avenues given to them by the Government. Sir, the report further says that despite the country's federal structure, the structure of revenue kept the

reins of resources in the Centre's hands and yet the management of the pandemic was left to the States, who were not equipped to handle it with their meagre financial or human resources. If you go through this, this is the real picture of equality. This is how the economic disparity has affected the entire nation, not only during Covid, but even before and after that. This is the real picture of equality among the richest, rich, middle class, marginalised and the poorest of the poor of the country. What a splendid achievement of this NDA Government for the past seven years! According to estimates of Centre for Monitoring Indian Economy, two crore Indians lost their jobs in April-May, 2021. In October, 2021, at least, 5.46 million Indians lost jobs and in November last year, six million salaried jobs were lost. There is no whisper in the President's Address about this alarming joblessness in the country due to policy paralysis of the Union Government. This Government assured that there will be a creation of jobs for two crore unemployed youth every year and this is the real picture that the Centre for Monitoring Indian Economy has assessed. Let us see what the hon. President has stated in paragraph 79 of his speech.

Only one line I would like to quote with your permission. I quote, "Today, the country's achievements and successes are as limitless as the country's potentials and possibilities." Sir, I mentioned para 79 of President's Address. But, according to OXFAM Report again, published in January, 2022, India falls in all international indices. For example, in the Human Development Rank, India's rank is 131 out of 189; in Hunger Index, India's rank is 94 out of 101 countries; Peace - 139 out of 163; Happiness - 144 out of 153; Healthcare - 145 out of 195; Gender Gap - 140 out of 156; Environment - 168 out of 180; Internet Quality - 79 out of 85; Water Quality - 120 out of 122; Press Freedom - 142 out of 180; Per Capita GDP - 142 out of 189; Health Expenditure as percentage of GDP - one of the lowest in the world. Expenditure on Education is among lowest in the world. National Education Policy of 1968 recommended for spending 6 per cent of GDP on education, but so far we have allocated only 3 per cent. ऐसी सफलता के साथ देश आज अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। 142 billionaires अमृत पी रहे हैं और देश की आम जनता जो पी रही है, वह अमृत नहीं है, बल्कि हलाहल है, जैसे समुद्र मंथन के समय प्रभु महादेव हलाहल पीकर नीलकंठ हो गए थे। हमारी आम जनता के नसीब में आगे जो हलाहल काल आ रहा है, उससे न जाने क्या भयंकर स्थिति पैदा होगी? सर, यह सरकार बोलती बहुत है, लेकिन इसकी असलियत क्या है, 'मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे ह्रदये तु हलाहलम्।' Sir, there are other achievements too of the Government. For example, the surgical attack on the federalism which otherwise is a basic structure of the Constitution, as ruled by the Supreme Court of India. The Home

Ministry has recently extended the jurisdiction of Border Security Force from 15 kilometers to 50 kilometers in the States bordering with Bangladesh and Pakistan, without having any discussion with the concerned States. This unilateral decision on the part of the Central Government is an attempt of coercion upon the elected State Governments having international borders. Similarly, the recent *Fatwa* proposing amendment to IAS Cadre Rules is arbitrary and a veiled attempt to centralize executive powers of the States. Already 9 Chief Ministers and 109 retired IAS/IFS/ITS officers have vehemently opposed this unilateral and arbitrary decision of the Union Government. Constitutional Heads in the Opposition-ruled States are behaving like political functionaries and interfering with the day-to-day administration of the States and challenging the policy decisions of the Governments of the Opposition-ruled States and day in day out they are coming out with press statements criticizing the State Governments. Sir, this is unprecedented and this is a surgical attack on our federal structure. This Government has forgotten the first Article of the Constitution of India, the very first Article. Article I of the Constitution says and I quote, "India, that is Bharat, shall be a Union of States not a unitary State". But, these steps are actually supporting to transform this country into a unitary state, to help strengthen the passage of totalitarianism. Sir, assault on Constitutional and statutory institutions like the Election Commission of India, CVC, C&AG, CBI are well known.

They are also being exploited for political advantage of the Ruling party and against the Opposition parties. Sir, most of these institutions have turned to be breeding grounds for selected group of retired Government servants who are not only being appointed by the Government to serve them beyond their service tenure, but also getting extension after extension in their extended service career. But, the Government is not too much satisfied with that only. This is why on the National Voter's Day, the hon. Law Minister said, "In the name of independence of judiciary, independence of Election Commission, independence of Legislature and Executive, if there is no coordination, then how will we work? How will one run the country?" Hence, the Government wants to have a committed judiciary, a conducive Election Commission and the agencies, so on and so forth, in the name of so-called coordination. The President's Speech has not addressed this growing problem of attack on time-tested institutions and authorities. Sir, in the name of economic reforms, the Government has emerged as a Bikreta Sarkar or a Seller Government in as much as it has decided to sell out almost all public properties. These are PSU banks, Insurance companies and even profit-making public sector

enterprises. Sir, PSU banks have earned net profit of Rs. 31,820 crores in one year, i.e., last fiscal 2020-21, which is the highest in the last five years. Sir, yet Government wants to sell PSU banks to private sector for which Banking Nationalisation Amendment Bill is reportedly in the offing. The Government policy is to privatise profits of public sector on the one hand and to nationalise losses of private sector on the other. I am giving one example. Vodafone Idea, a private telecom company owes the Government Rs. 1,70,000 crores whereas Rs. 16,000 crores shall be invested by the Government in their share capital. Is this not crony capitalism? On the one hand, bad loans written off by public sector banks from 2001 to 2021 amount to Rs. 9,88,160 crores. In the year 2021 alone, Rs. 1,31,894 crores were written off. On the other hand, the public sector banks have reduced rate of interest on savings account from 6 per cent to 2.9 per cent and in Fixed Deposits from around 12 per cent to 5 per cent in detriment to the interest of the common people; mostly senior citizens are affected by this. Sir, this is something like rob peter to pay paul. In spite of such writing off bad loans, it has not come down. According to estimates, new bad loans during the year 2020-2021, figured as Rs. 2,02,879 crores. This is a surprising figure. As on 31st March, 2021, loan amount due in top four NPA accounts of public sector banks stands at Rs. 89,300 crores. Who are these big fishes, who have eaten public deposits from public sector banks? Why has not the Government shown any courage to name them, not to speak of taking criminal action against them for open loot of public money? Sir, I am sorry to say the President's Address does not reflect anything about the measures supposed to be taken by the Government to arrest this unholy nexus. Sir, such is the case of revelations made by International Consortium of Investigative Journalists, through Panama Papers, Paradise Papers, and of late, the Pandoras Papers. More than a thousand Indians have stashed black money outside the country in the offshore tax havens. How many of them have been arrested? How much black money has been recovered; publish a White Paper. I urge upon the Government to publish a White Paper, the way Mr. Pranab Mukherjee, when he was the Finance Minister in 2012, published a White Paper on black money. If this Government has the courage to inform the people about the action taken by them to unearth black money, let the Government publish a White Paper on black money following the footsteps of late Pranab Mukherjee.

2.00 P.M.

Sir, before I conclude, I would like to refer to a portion of speech delivered by hon. Justice D.Y. Chandrachud, an eminent jurist of Supreme Court, published in the *Indian Express* on August 29, 2021 wherein the hon. Justice said, "Speaking truth to power is not only a right but also the duty of every citizen and the way to achieve this is by strengthening public institutions such as ensuring the freedom of the Press and the integrity of elections, acknowledging and celebrating the plurality of opinions and by committing oneself to the search for truth as a key aspiration of society." This is in public domain because it was an online address. Hence, if I believe in the freedom of Press, I can't characterize the media as 'supari' media and even if I have no faith in this Government, I can't term this Government as 'supari' Government because that will be an irresponsible act on my part as a parliamentarian. Justice Chandrachud also said one line more, "One cannot only rely on the State to determine the truth as it may not always be free of falsehood." In this quest for truth, Sir, I am asking myself as to whether I should believe that New York Times is lying, Citizen Lab is lying, Amnesty Tech is lying, French Government is lying, German Government is lying, US Government is lying, Apple and WhatsApp who have sued NSO are lying and only Government of India stands in splendid isolation with the truth about Pegasus. This is my submission. With these words, Sir, I conclude. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, the next turn was for Shri Tiruchi Siva*ji* but he has very kindly consented to allow Prof. Ram Gopal Yadav*ji* to take his spot. So, now I will request Prof. Ram Gopal Yadavji for his words. Thank you.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : हमारी संसदीय परंपरा और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं, उसके आधार पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं परंपरा का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए समर्थन तो करता हूं, लेकिन इसका समर्थन करने का मन नहीं है, क्योंकि पूरा अभिभाषण विरोधाभासों से भरा पड़ा है। इसमें एक पक्ष कहा गया है और उसके दूसरे पक्ष को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया एक दस्तावेज होता है, जिसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं, यह बात तो सब जानते हैं। जो वास्तविक स्थिति है, वह एक दर्पण की तरह होनी चाहिए कि हम कहां ठीक काम कर रहे हैं और कहां कमी रह गई, जिसको हम ठीक करके बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को छुपाओगे, तो वे कमियां बढ़ती रहेंगी और केवल हम वाह वाही में कुछ अच्छाइयों की ही बात करते रहेंगे, इससे

काम चलने वाला नहीं है। देश का हित तो इसी में है कि सबके कल्याण के लिए जो प्रगतिशील कदम उठाए जा रहे हैं, वे सब तक पहुंचें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के चौथे प्वाइंट में यह कहा गया है कि मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने अतीत से कुछ सीखने की कोशिश की है या नहीं? सारी दुनिया जानती है कि जब-जब लोगों ने अतीत में कुछ गड़बड़ की है, तो देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि और देशों को भी भुगतना पड़ा है।

हम लोगों को भी भुगतना पड़ा, हमारा देश बंट गया, उन विभाजनकारी नीतियों को अब इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक चालू करने की कोशिश हो रही है। एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए, वहां पर केवल दंगा-फसाद हो, इस तरह के बयान अगर देश के गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्य मंत्री तक रोजाना देंगे - भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि देश का गृह मंत्री या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्य मंत्री इस हद तक गिर कर असंसदीय भाषा का, गाली-गलौज तक का प्रयोग अखिलेश के लिए करेगा। एक अकेले अखिलेश की वजह से प्रधान मंत्री से लेकर बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है, जो पानी न मांग रहा हो, वह भागा-भागा फिर रहा है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से रैलियां खत्म करवा दीं, वरना इनके लोग कहीं पर घुस नहीं सकते थे और तब भी रोज़ाना पिट रहे हैं। आप वीडियो देखिए, वे रोज़ाना पिट रहे हैं। जब अखिलेश के खिलाफ गाली-गलौज़ करोगे, तो लोगों का रिएक्शन होगा । ये लोग यह नहीं समझते हैं कि ऐसा करने से लाभ नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का वोट यूनाइटेड होता है। जब अखिलेश को गाली देंगे, जब उसको गाली देंगे, पूरी कौम को गुंडा कहेंगे, तो आपको उस कौम का वोट कैसे मिल जाएगा! अगर 100 वोट होंगे, तो वे 1,000 वोट दूसरों के डालेंगे । आप उससे कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। पूरे देश में आपकी नीतियों को लेकर बात नहीं हो रही है, बल्कि गालियां दी जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि यह गुंडों की पार्टी है। एक उप-मुख्यमंत्री, एक मंत्री किस सीमा तक, कैसे बात करते हैं? माननीय गृह मंत्री जी ने चित्रकूट में कहा - अखिलेश कितना ही जोर लगा ले, मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के चंदे में चोरी कर रहे थे। अखिलेश की सरकार आएगी, तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी और मैं सदन के माध्यम से यह बात कह रहा हूं। इतने जिम्मेदार लोग, इतने गैर-जिम्मेदाराना बयान करें, तो यह अच्छा नहीं है। मैं कभी इस तरह की बात नहीं कहता हूं, लेकिन रोज़ इस तरह की बातें सुन रहा हूं, इसलिए यहां कह रहा हूं, बाहर तो यह भी नहीं कह सकता हूं। यहां पर समझदार लोग बैठे हुए हैं, सारे देश के लोग बैठे हुए हैं, हालांकि प्रधान मंत्री जी के साथ ज्यादातर लोग चले गए। मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है, विष्णु पुराण भी पढ़ा है, तमाम पुराण पढ़े हैं, लेकिन मलिक साहब से आज मैंने मोदी जी का पुराण भी सुन लिया और वे भी चले गए। प्रस्ताव रखने वाले, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को कायदे से सदन में उपस्थित रहना चाहिए कि उनके प्रस्ताव पर कौन आदमी बोल रहा है और वह क्या कह रहा है। उन दोनों में से एक भी यहां पर नहीं है। प्रस्ताव रखने वाली हमारे जिले की माननीय सदस्या कहां हैं? बहन जी ने औरैया जिला बना दिया, बिना मांगे जिला बना दिया, छोटा-

सा जिला इटावा था, उसके टुकड़े करके औरैया जिला बना दिया! ये हमारी पार्टी की अध्यक्ष रही थीं, यह अच्छा है कि आपने उन्हें राज्य सभा का सदस्य बना दिया। वे बहुत सी बातें बोल रही थीं । सर, मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। आप रोज़ाना नारा देते हैं, सरकार के लोग रोज़ाना नारा देते हैं कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'। अब उसमें 'प्रयास' और जोड़ दिया है। मेरा कहना है कि सबका विश्वास लेने की कोशिश होनी चाहिए, केवल नारे लगाने से कुछ नहीं हो सकता है। क्या आप सबका विश्वास लेते हैं? अभी जब खरगे साहब बोल रहे थे, तो इधर से मंत्री लोग विरोध कर रहे थे। मैं काफी समय से देख रहा हूं कि कभी मंत्री नहीं बोलते थे, हालांकि seasoned मंत्री अभी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में बोलते हैं। नक़वी साहब बोल रहे थे, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर लगातार बीच में इंटरवीन कर रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुमत आपका है, जैसा चाहे, वैसा निर्णय आप करेंगे। संसद में आपका बहुमत है, आप जैसा चाहे, वैसा कानून बना सकते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, तो वह विरोध करेगा। उसमें नाराज़गी की क्या बात है? फैसला तो आपको करना है। आप जैसा चाहते हैं, वैसा निर्णय करेंगे और वह निर्णय होगा ही। फिर विपक्ष को अपनी बात कहने या विरोध करने का ही तो हक है।

हो सकता है कि उससे आपको कुछ लाभ हो, लेकिन आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इधर के लोग नाराज हो जाएंगे, तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन अगर आप नाराज हो जाएंगे, तो आप हम लोगों का बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग गुस्सा मत किया कीजिए, गुस्सा करने का अधिकार विपक्ष को ही होता है, सत्ता पक्ष को नही होता है, सत्ता पक्ष तो सुने। भारी बनिए और सुनते रहिए। जो निर्णय लेना है, वह तो आपको ही लेना है, इन्हें तो कहना है, इसलिए कहने दीजिए, लेकिन आप सुनिए तो।

इसमें यह सही बात है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोरोना काल में बहुत शानदार काम किया, हम इस पैरा से पूरी तरह से सहमत हैं। आप लोग लगातार यह कहते हैं, सरकार यह कहती है कि हमने वैक्सिनेशन में रिकॉर्ड बनाया है। आप यह बताइए कि देश की आबादी ही 126-130 करोड़ है, तब क्या इंग्लैंड जैसा देश, जिसकी आबादी 15-20 करोड़ होगी, वह 130 करोड़ का वैक्सिनेशन करा सकता है? वह दस बार कराएगा, तब हिंदुस्तान के बराबर आ पाएगा। आप रिकॉर्ड की बात क्यों कर रहे हैं? जब दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो स्वाभाविक है कि आप सबसे ज्यादा वैक्सिनेशन कराएंगे। अभी प्रस्ताव करने वाली सदस्या कह रही थीं कि देश में सबसे ज्यादा टीके हमारे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों को लगे। जब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसकी आबादी ही 26-27 करोड़ है, तब उसका वैक्सिनेशन तो ज्यादा होगा ही। यह लगातार आता है कि रिकॉर्ड बनाया, परंतु रिकॉर्ड तब बनाओ, जब सटीक बात हो। इज़राइल ने एक साल पहले 100 परसेंट वैक्सिनेशन कर लिया था, आप अभी तक नहीं कर पाए। रिकॉर्ड यह होता है कि आपने कितने परसेंट लोगों का वैक्सिनेशन कराया। देश बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि आपकी संख्या ज्यादा होगी। उसमें कौन-सा रिकॉर्ड बन गया? आप हर जगह रिकॉर्ड की बात करते हैं। देश की बिना पढ़ी-लिखी जनता भी ये बातें समझने लगी है, इसलिए आप उन्हें मूर्ख मत समझिए, वे यह सब जानते हैं।

सर, अभी हम लोगों ने हैल्थ सेक्रेटरी से और आई.सी.एम.आर. के डीजी भार्गव साहब से पूछा था कि क्या बूस्टर डोज़ लगानी जरूरी है? उन्होंने कहा कि आई.सी.एम.आर. के हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, वे इसका जवाब देंगे। उन्होंने सीधे कहा कि बूस्टर डोज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता ही नहीं है, तब यह बूस्टर डोज़ क्यों लगाई जा रही है? क्या आपको मालूम है कि यह क्यों लगाई जा रही है? यह इसलिए लगाई जा रही है, क्योंकि ये जो वैक्सिनेशन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इनको इससे इतना लाभ हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चार पैसे की वैक्सीन के कितने पैसे लेती हैं? केवल इनकी डेवलपमेंट में पैसा लगता है, इसलिए शुरू में उसकी ज्यादा कीमत होती है और बाद में वह कीमत कम हो जाती है, लेकिन ये कीमत कम नहीं करती हैं। ये गवर्नमेंट की ट्रेज़री का सारा पैसा खा गए, वैक्सिनेशन के मालिक - भारत बायोटेक और पूनावाला। आप देखिएगा कि जब दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों के नाम निकले थे, उसमें पूनावाला सातवें, आठवें नंबर पर पहुंच गया। उसको इससे इतनी आमदनी हुई कि वह सिर्फ वैक्सिनेशन के पैसे से वहाँ तक पहुंच गया। जब हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, हैल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल की उपस्थिति में हैल्थ कमेटी के सामने, हमारे मेम्बरान के पूछने पर यह कहते हैं कि बूस्टर डोज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर बूस्टर डोज़ क्यों लगाई जा रही है? मेरा दोनों बार वैक्सिनेशन हो गया था, उसके बाद सेकंड वेव में मुझे कोरोना हो गया, अभी चार दिन पहले फिर कोरोना हो गया। हम वैक्सिनेटिड हैं, डबली वैक्सिनेटिड हैं और जो बूस्टर लगाए हुए लोग हैं, उनको भी हो गया। कहने का मतलब यह है कि जान को खतरा नहीं है, लेकिन कोरोना होने से, उससे इन्फेक्टिड होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह बूस्टर डोज़ लगाने के लिए अनावश्यक रूप से गवर्नमेंट के एक्सचैकर पर और लोड डालने का काम कर दिया गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगा रहे हैं।

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की यह योजना बहुत अच्छी है, लेकिन प्रश्न यह है कि डॉक्टर ही नहीं हैं। अस्पताल बने हुए हैं, वैलनेस सेंटर्स बन गए, 80 हज़ार से ज्यादा हैं, लेकिन अभी कोरोना काल में जब कहीं जगह नहीं थी, कहीं बैड नहीं मिल रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में, यही गाजियाबाद में, आपने टीवी पर देखा होगा कि कोई ऐसा जिला नहीं था, जहाँ प्राइमरी हैल्थ सैंटर में कागज पर डॉक्टर है, लेकिन मौके पर नहीं आ रहा है। है ही नहीं कोई, कोई जाता ही नहीं है। इतना mismanagement है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपके मंत्रिमंडल में आपस में इतनी लड़ाई है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई देखने वाला नहीं है कि ये जो बने हुए हैं, इनका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम केवल कागज पर लिखते रहे कि इतने Wellness Centres बन गए, लेकिन उनमें इलाज कहाँ मिल रहा है! अभी तीन महीने पहले डेंगू आया। फिरोजाबाद में कोई नए किस्म का डेंगू आ गया। दो महीने के अंदर 1,500 आदमी मर गए। हमने यहाँ भार्गव साहब से कहा, तो उन्होंने एक टीम भेजी। उन्होंने कहा कि यह डेंगू इस नाम का है और यह थोड़ा हट कर है, फिर इसका इलाज हुआ। वहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं थी, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था और आदमी मर गया, जैसे आपने देखा कि कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के क्या हुआ था! उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री को कानून मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि

सीएमओ टेलीफोन नहीं उठा रहा है। बाहर लोग मर रहे हैं, अस्पताल में कोई पहुँच नहीं पा रहा है और सीएमओ मिनिस्टर का टेलीफोन नहीं उठा रहा है। ऐसी बदहाली रही है। इतना mismanagement रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लाख आदमी मरे और 23 हजार दिखाया गया। ऐसे में उन लोगों को कोई मुआवजा कैसे मिल सकता है? आप गाँव-गाँव जाकर गिन लीजिए कि कितने लोग मरे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के लिए कह दिया, तो जहाँ लोग मरे, वहाँ यह दिखाया गया कि इनको पहले से बीमारी थी, ये इससे मर गए, ये हार्ट अटैक के कारण मर गए, जबकि सब कोरोना से मरे। कहा गया कि इनको साँस की दिक्कत थी, जबकि कोरोना में साँस की दिक्कत तो थी ही, लेकिन कोरोना के कारण मृत्यु नहीं दिखाई गई। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर से पूछा, हमारे गाँव में जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी, वहाँ पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा निर्देश है कि इसको कोरोना से मत दिखाइए, बल्कि और तमाम जो बीमारियाँ होती हैं, आप कहिए कि इनकी वजह से मर गए, जबकि व्यक्ति कोरोना के कारण अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। उस समय स्थिति इतनी भयानक रही है, लेकिन कहीं पर भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया गया है।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश)**:** गंगा नदी में लाशें किसकी थीं?

प्रो. राम गोपाल यादव : गंगा में तो खैर कौव्वा नोंच गए, उसे तो सारी दुनिया ने देखा। यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को यह कहना पड़ा कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं कायम हो गया है, जिसने चैनल पर गंगा में लाश तैरती हुई दिखाई। यह कमेंट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज का था, जो निकट भविष्य में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे।

मैं आपको बता रहा था कि हालत यह हो गई थी, जिसका कहीं ज़िक्र नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय राम गोपाल यादव जी, आपके 15 मिनट complete हो गए।

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं ही तो बोलूँगा। कितने मिनट हो गए?

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आपके 15 मिनट थे, 15 मिनट complete हो गए।

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं एकाध मिनट और बोलूँगा। आगरा का हमारी पार्टी का एक अध्यक्ष था, उसके बच्चे का रोते हुए टेलीफोन आया कि वह दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही है, अगर यह मिल जाए, तो वे बच जाएँगे। मैंने पूछा कि यह कैसे मिलेगी, तो उसने बताया कि यह डीएम साहब के कहने से मिलती है। मैंने डीएम, आगरा को टेलीफोन किया। डीएम, आगरा ने कहा कि अभी एक इंजेक्शन उपलब्ध है, मैं उसे उपलब्ध करा रहा हूँ, और कल करा दूँगा। एक तो मिल गई, लेकिन उस

वक्त दो चाहिए थी। यह शुरू में दो ही लगती हैं। रात में वह खत्म हो गया। वह तो मात्र 45-50 साल का था। कहीं यह दवा ही नहीं मिली। यह योजना अच्छी है, लेकिन न डॉक्टर उपलब्ध है, न दवा उपलब्ध है, तो मरीज तो मर ही जाएगा। आप जो 5 लाख वाली बात कह रहे हैं, उसका लाभ कोई तभी उठा पाएगा, जब कोई दवा देने वाला होगा, दवा होगी, डॉक्टर होगा। अब एम्स में कोई आ नहीं सकता है, यहाँ वह लाभ नहीं मिल पाएगा। निजी अस्पताल इतने महँगे हैं कि कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई गरीब तो क्या, कोई सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहाँ इलाज नहीं करा सकता, हालत इतनी खराब है। कहीं इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है।

मैं एक और बात कहना चाहूँगा और फिर अपनी बात खत्म कर दूँगा। इसमें 14वें प्वाइंट में बाबा साहेब अम्बेडकर को quote करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा है, "मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों। इसलिए आज सरकार की नीतियों में गाँव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।"

क्या व्यवहार में भी ऐसा है? क्या यह सच नहीं है कि इन्हीं वर्गों के खिलाफ़ काम हो रहा है, इन्हीं वर्गों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है और इन्हीं का हक छीना जा रहा है, इन्हीं का हक मारा जा रहा है। अभी सात-आठ दिन पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी के Professors और Assistant Professors का एक इंटरव्यू पढ़ा था। SC, ST and OBC के लिए, reserved category के लिए जो 31 पोस्ट्स थीं, उनके लिए लिखा था, 'No suitable candidate found.' And, all the posts were transferred to the General Category. हर जगह यही बात कही जा रही है कि कोई suitable candidate नहीं है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम ये सब काम कर रहे हैं। क्या केवल लिखने से ही यह हो जाता है?

महोदय, जातिवार जनगणना करवाने के लिए बिहार के मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल एवं बहुत सारे अन्य लीडर्स आए। अखिलेश जी ने भी चिट्ठी लिख कर अपनी बात कही। मैं जानना चाहता हूं कि जब जनगणना हो ही रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? पहले भी जनगणना हो चुकी थी, तो अब उसको देने में क्या दिक्कत है? लेकिन कैबिनेट ने डिसीज़न दे दिया कि यह नहीं हो सकता है। प्रतिस्थापित करने वाले कह रहे हैं कि 27 OBCs, 20 SC/STs के मंत्री बना दिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन मंत्रियों को मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है। जब Backwards and SC/STs के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो इनके लिए कोई मुंह खोलने वाला है या नहीं है? एक आदमी भी उनके लिए नहीं बोलता है। इस तरह के representations से इन communities को कौन सा लाभ हो रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सही स्थिति नहीं दर्शा रहा है। देश की बहुत खराब स्थिति है। देश के कुछ राज्यों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस तरह के लोग शासन कर रहे हैं, वहां की जनता घुट रही है। वे लोग रात-रात भर खेत को गायों और सांडों से बचाने के लिए जागते रहते हैं। गांव-गांव में ऐसा हो रहा है, हालत इतनी खराब है। आधी से ज्यादा फसल जानवर खा जाते हैं और जो किसान अनाज पैदा करता है, उसकी स्थिति भूखे मरने की बन गई है, ऐसे हालात हो गए हैं। अंत में, संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का

समर्थन तो करूंगा, लेकिन शुरू में ही मैंने कह दिया था कि इस अभिभाषण का समर्थन करने को मेरा मन नहीं करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. Sir, I rise to support the Motion of Thanks to the hon. President for the Address he has delivered to both the Houses of Parliament, moved by my esteemed colleagues, Madam Geeta and seconded by Mr. Malik, both of whom are not here now in the House. But, as per the conventions, we do our duty of thanking the President. In the process of my speech, however much I try, I hardly find anything to appreciate in his entire speech to the Members of Parliament except two things. One is the couplet from Thirukkural which the hon. President quoted and the other is from Dr. Baba Saheb Ambedkar. Other than these two things, I think nothing is there to appreciate or relish in his speech. The bed-time stories of the children are built on maximum imagination but what they are telling now exceeds even bed-time stories. Nothing is in practice. Let me quote what the President in his Address told about Dr. Baba Saheb Ambedkar. I quote: "My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. Democracy is not merely a form of Government, it is essentially an attitude of respect and reverence towards one's fellowmen." Sir, it is only in letter and not in spirit. I am reminded of a famous maxim about democracy, which is, democracy by the people, for the people and of the people. Yes, this Government was elected by the people but it conveniently forgot its promise of working for the people, and also forgot that it should be a Government of the people. All the policies and actions of this Government are anti-federal and anti-secular. When our founder leader Anna assumed the Office of the Chief Minister, the journalists, during his first interview in Delhi, asked him, "What is your economic policy?" Anna said, 'Tap the rich and pat the poor.'

That was a very famous policy that he told the people and to the entire country. But now this Government is tapping the poor and patting the rich.

Sir, when you say the GST collection is Rs. 1,14,000 crore in one month, who has paid that? It is the poor and the middle class people. For whatever they buy, however they live, they pay tax to the Government. But what has happened? The Government, instead of addressing very core issues like the crumbling MSME sector, the impact of the Covid, the increase in the prices of essential commodities, the enormous increase, 69

times in one year in the petroleum products -- the Government has earned Rs. 4.91 lakh crore by way of this; from 2014, this Government has earned Rs. 25 lakh crores by way of hiking the petroleum products -- instead of addressing all these issues, you are prioritizing to fighting off the minorities' rights, values and beliefs. Sir, it is very saddening. It is an agrarian economy. Basically, India is an agricultural country but now it is becoming a corporate country. What happened to our farmers? They were sitting in the hard summer, bitter cold and the rains for one year because of your Farm Acts, and you repealed it only because of the five State elections. -- anybody would accept that it is not out of concern towards the farmers -- that too after they sacrificed 700 lives. The Government should have been empathetic, not even sympathetic, 'empathetic'. When you quote Dr. Baba Sahab Ambedkar that 'We should have respect and reverence towards one's fellow man', the Government's duty is to protect and save every life of the citizens in this country, whereas, 700 lives were lost during that struggle. But the Government, at last, repealed, that too, without a discussion in the House. But what is the result? Are they happy about it? Yesterday, the *Samyukt Kisan Morcha* who have fought for the farmers have given a Press release, 'Government betrays farmers once again; Budget exposes empty promises of Government on MSP and doubling farmers' income.' It is because the Government said, 'we would increase the farmers' income by 200 per cent but now it is not so. They said, 'by 2022.' We have reached 2022 but the farmers' income has not been increased. Their input costs have increased. The DAP and urea which was Rs. 1,300 is now Rs. 2,000. Which was Rs. 700 rupees is now Rs. 1500, whereas the MSP has not been increased. Basically, eighty per cent people of the country are basically agriculturists. During the economic recession, India survived only because of two things. One is, public sector and the other is agricultural sector. Even during the Covid pandemic, India had food sufficiency because of our agriculture but you are killing it; so also the public sector. You are giving 5G to the private sector but not even 4G to BSNL and MTNL. It is a silent way of killing the public sector, BSNL and MTNL. So, everyone would migrate from BSNL to the private sector. Of course, when everyone is living in a digital world, we are for 5G, whereas they are not even able to provide 4G. They have enough infrastructure. The infrastructure of the BSNL is being utilized by other private networks. But you are giving them 5G. So, what is your intention actually? You are patting them like anything. Take the LIC which has got an asset of Rs. 34 lakh crores and which is, of course, sharing its profit with its policy holders. It gives dividend to Government. But you are going to kill it. You take the money. The policy

holders are protected only by LIC, and you are going to take the money and fulfil the pockets of the corporates. So, what is going on in this country?

Sir, India is said to become the youngest country, the largest democracy is going to be the youngest country in the world. In what sense? Sixty-four per cent of its population is going to come under the working-age group. What are the plans that we have got? When you introduced the 'Make in India' programme, you said that 'five crore people are employed, we will make it ten crore.' But now it is 2.5 crore. You were assuring yesterday in the Budget that 'We will give 60 lakh jobs in five years, that is, 12 lakh jobs in one year.'

The Finance Minister says very happily that it is a blueprint for the next 25 years while the Prime Minister says it is for 100 years! Sir, what are they talking; to whom are they talking? The poor are becoming poorer, the rich are becoming richer. The richer are now becoming corporates. That is what we are witnessing in this country now. According to numbers released by the Ministry of Commerce and Industry on 14th January, 2022, not much earlier, the provisional annual rate of inflation is 13.56 per cent for the month of December, 2021 whereas in 2020, it was just 1.95 per cent. It is their statistics, Sir. This is the state of inflation. The prices of essential commodities are increasing. People don't have enough income. The way they have handled various issues, people have been suffering. They don't have jobs. How are you going to tackle unemployment? You don't address those issues. You keep talking about other things. You are patronizing the corporates. The burden of inflation is borne by the middle class and lower class only. What happened to the MSME sector? When it was crumbling and there was a dire need for boosting it up, it suffered a severe blow because of demonetization and the hasty implementation of GST. The States surrendered their sovereignty of collecting taxes, but the promise that was given by the Union Government that it would give its due share to the State Governments has not yet been fulfilled. The due share has not been paid to many States. Even my State has been asking for it. Many representatives of the State here would tell you that the GST share due from the Central Government has yet not reached them. Then what are you doing with the money that you collected? You are only waiving off the NPAs of corporates. If a poor student who has taken an Education Loan is not able to pay his EMIs after a few years, he is harassed. His loan is treated as NPA, his CIBIL score is affected and they tell him that he won't be able to take a loan from any bank anywhere in India. So, if a poor boy who has taken a loan of Rs. 4 lakh is not able to return that money, he is harassed whereas

loans worth thousands of crores of rupees taken by corporates are waived off. What is the policy that this Government is following? That is why I said, you are tapping the poor and patting the rich. This is not a socialist country. You are scared of many words, as the Leader of the Opposition said. You are scared of many names and many words, like socialism, secularism and federalism. You are scared of all these words.

Sir, these are all very, very important things. We are not just making accusations or allegations. This is what is happening in this country today. When a Government is elected, its duty is to take the country much forward than it was, but it is dragging the country backwards. India is thickly populated and its people who are mostly young and poor are not being taken care of. What is the future of this country?

Sir, I now wish to highlight three important issues. In my State, Tamil Nadu, the sad plight that fishermen have been enduring is a continuous process. Today is the 2nd of February. On 31st of January, 2022, 21 fishermen from Nagapattinam and Puducherry were arrested by the Sri Lankan Navy. Three of their boats were seized. Sixty-eight fishermen had been arrested earlier, but thanks to the initiation and intervention by our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, and of course, the External Affairs Minister, they have been released, but they are waiting for repatriation. Now, these 21 fishermen have been arrested, three boats have been seized and we do not know what is going to happen to them. So, all through the year, when fishermen are imprisoned in Sri Lanka, their families are languishing here. We have been suggesting that the Union Government must find a permanent solution to this problem. Even yesterday, our Leader, Mr. Stalin, wrote a letter to the Government asking them to find a solution. It cannot just happen that our fishermen get arrested every time and we go and engage in talks with them. The fishermen's issue needs to be settled fast. The Government must give priority to such issues. You are not doing that. Rather, you are attempting to encroach upon the powers of the States.

You have an aversion towards some regions, some languages. It is anti-lingual and anti-region. India is famous for its unity in diversity. But in practice it is not so. You are totally dispensing with some languages. Hindi is being imposed either this way or that way. I even represented a grievance to the Home Minister. It was a genuine representation. In the CRPF, for non-paramedical staff, just table boys, sweepers and cooks, the qualification is 10th standard. But the examination is only in Hindi and English. You cannot expect students from non-Hindi speaking States who have studied just up to 10th standard to appear in English test. What we suggest is this. All these examinations

should be held in regional languages recognized by the Constitution. The 8th Schedule of the Constitution has 22 languages. Do that for this kind of examination. You should not just pay lip service to that by saying that we support and encourage other languages. No. You are actually killing other languages.

The Republic Day Parade ceremony is which all of us have been celebrating, especially in this year which is the 75th year. Every year all the States will not get a representation. We are aware of that. But this is a special year. It is the 75th year. The Tamil Nadu Government gave seven designs. The theme was Tamil Nadu's participation in the freedom struggle. There were four rounds of scanning by an Expert Committee. They say that it is an Expert Committee. The Expert Committee has not come down from the sky! It is only constituted by you. The Committee constituted by you drafted the National Education Policy which was not accepted even by the academicians. This Expert Committee approved it up to three stages. We have given the history of Rani Velu Nachiyar, the first ever queen who won back her territory which she had lost to the British. Everyone had lost their territory and died. But she was the only person who regained the territory which she had lost to the British. Everyone knows Bharati, the patriotic poet. So is V.O. Chidambaranar who first launched Swadeshi Steam Navigation. Then you have Marudu brothers who helped Velu Nachiyar. All these things were not approved saying that it is unacceptable. Where can we go and say this? I was watching the Republic Day Parade on TV thinking something better would be there. But I saw only saffron-clad saints walking on a tableau. Why are you rejecting us? It has been happening for long that patriots and others from South Indian States, especially from Tamil Nadu, are not recognized. Why all these years it has happened? Again, the Chief Minister wrote to the Prime Minister himself. Sir, it is very important. But they did not allow. There is a proverb that you cannot stop a marriage just by concealing a comb. You didn't accept our proposal for the Republic Day Parade. Do you know what our Chief Minister did? He just arranged the rally of the same tableau across Tamil Nadu in all the districts. It was in every street. It reaches the rural areas. Had it been here it would have been for some minutes but now it is going on for days telling our people all these things. I have spoken in this House untold stories of the people who remained hidden in history. The children should be taught about them in the schools. Only one more point, Sir. Another of my colleague would speak later on with some points. I have got only one more point.

By recent amendments to the All India Services cadre rules, what has the Government done? What was in existence earlier won't be there hereafter. What is that? The Central Government without the consent of the State Government can call any IAS, IPS, IFoS officer to its service. Sir, it is again transgressing the rights of the States. How can you do that? And by whose authority can you do that? Ours is a federal structure. Did you consult any of the States? No. There is a group of former All India Services officers. Some 100 officers have made a very, very clear statement.

They have said that in the federal structure of the Union of India, the Union and States exist as distinct and separate entities though they work in tandem to subserve common constitutional objectives. Maintaining this balance is critical to good governance. Sir, they came to power saying, 'Minimum Government, Maximum Governance'. But now the Government is maximum; governance is minimal. ...*(Interruptions)*... Yes, no governance. He knows better. ...*(Interruptions)*... Proposed amendments to the Cadre Rules of all the three All India Services seek to empower the Union to pick and choose any AIS Officer working in the States to be withdrawn from their services in the State of their allotment hits at the very core of the constitutional scheme of Indian federalism. Sir, these All India Services are not the creation of the Executive. It is by the Constitution. Their experience in the State would help. But if at all you take them here, they would be serving only the Centre and they would lose interest in the States. Hereafter, States would also suspect All India Service officers. They would rely more on their own selected State officers. This is not an indication of federalism. This is not good at all. You enact draconian laws. With UAPA, you imprison social activists and minorities, and you also take away the rights. What is going on in this country after this party has assumed power and the President has also addressed, I could simply say that democracy is in peril, secularism is at stake, federalism is targeted, State rights are encroached and transgressed, economy is shattered, minorities are unsafe and public sector is crushed. This is our experience and nothing else. I will say only one thing. When our founder leader Anna spoke in the same House, he said this. ...*(Interruptions)*... It is great to know, as Mr. Jairam Ramesh says, that the place from where I am speaking because of Covid, was the place from where my founder leader Anna spoke. He said, "Carry on, but remember. Carry on because people have given you a mandate but remember the people are watching you." After two years, they will teach you a lesson. All those who are suffering will say what

they have to. They say, "*Ezhayin kanneer odiya vazhayur*" in Tamil, which means, the tears of the poor are much sharper than the sword. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. K. Keshava Rao; not here. Then, Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya. You have nine minutes.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am really honoured to get this opportunity to speak on the Motion of Thanks. I thank the hon. President for taking the trouble of coming to the Parliament to address the Joint Session, but I really cannot support the Motion after hearing the mover and the seconder of the Motion. The mover and the seconder of the Motion have made their ideas very clear about what is the perception of the President's Address. I was hearing the chanting of a particular name which makes me apprehensive of a situation which I have heard about 1930s in a particular period of time when a particular person was projected to be the hero of the world, ruler of the world, best person in the world and everybody was made to say, "Hail that man". Here, we really hear the same sound. That creates the danger and that danger is reflected in the speech of the hon. President. Here, the hon. President does not speak of the basic realities of our country.

The basic reality of our country is completely different than the rosy picture which has been sought to be projected by the deliberations of the hon. President. You would not find a mention that why the *kisans* of the country had to sit for one year and then the Acts were repealed most surprisingly. Those Acts, which were passed by both the Houses of the Parliament, were repealed on *Mann ki Baat.* It was not even discussed in the Cabinet before repealing. Is it really the democratic process? We want to know what had happened in the meantime. Why could a particular gentleman, honouring the Chair of the Prime Minister of India, on his own could decide to repeal the Acts, which were passed by both the Houses, without having a proper discussion in the House? This relates to a basic question of the Indian democratic system. I would refer to that a little later.

Now, I find everybody is very much hoary about the covid situation. Does the vaccination really answers all the problems of the covid situation? The covid situation has ruined our country and the poverty has increased. More than 33 crores of people have gone below the poverty line. Is there any reference to that? How could it be recovered? Nothing is mentioned. Ultimately, it is unfortunate that they are claiming

that they have given food to everybody but I know -- because of a particular case before the hon. Supreme Court -- that the hon. Supreme Court directed the Government to run the community kitchen so that the cooked food can be provided to the poorest of the poor people. That itself indicates that the so-called claim of feeding 80 crore of people is only on papers. In reality, you have to go down to them. You have to think of opening the community kitchen, which has been set as an example by the students and youth of West Bengal. They have shown how the poor people can be fed with cooked food during this crisis.

Now, we have already seen that there are international reports which do not get any reflection in the President's Address. International reports say that inequality in India has increased, widened up much during this period. More than 50 per cent of the world's poor people belong to India. How do you address this? What is your scheme? How do you think that we can really recover these people and bring them above the poverty line? There are countries in the world which have been successful in bringing all the people above the poverty line, which you have no scheme to speak of. Sir, 80 per cent of the Indian households have suffered income loss. What is your scheme? How do you think that these people could be given the source of income so that they can survive? You all talk of certain things which, ultimately, enrich the rich people. We have seen that this is the international report which has been referred to by Oxfam and the Economist Pickethy's report that the maximization of the profit during this period has gone in favour of few families and few Indians have really got their place in the list of top billionaires of the world and a majority of the Indians have gone down below the poverty line. What is your plan? This is really lacking. We are seeing that if these inequalities are not addressed to, the Indian democracy is definitely going to suffer a lot. To ensure that these people can not raise voice of sufferings, you are taking recourse to absolute oppressive measures. You are trying to destroy the Indian federal structure. I repeat, when in 2014 people gave you the mandate, people gave you the mandate not to extol an individual's fame and favour. People gave you the mandate to ensure that you carry out the constitutional dictums. You have to fulfil the constitutional dreams. But, we find that in the name of fulfilling constitutional dreams, you are destroying the secular structure of the country. You are hailing that you could build up *Ram Mandir*. Is this the duty of the Prime Minister of a secular country that he would go to *Ram Mandir*, he would go to *Kashi Vishwanath* and appeal to the people, "Follow your Hindu culture" and thereby create hatred against the minority community of the country?

Sir, democracy did not think of this. Kindly go to the debates in the Constituent Assembly and you will find that it was the responsibility of the State and the Government to ensure complete freedom, free from any fearness to the minority community. Now, in the name of 125th years of birth of Netaji Subhas Chandra Bose, you have a statue over there at the India Gate. I welcome the installation of the statue, but you do not welcome the philosophy of Netaji Subhas Chandra Bose. Netaji Subhas Chandra Bose not only had said that the minorities would be respected, they would be given equal share. He had practised it. Have you practised it? By only installing a statue, you cannot really deny the philosophy of the man. If you really want to show respect, please follow the philosophy of the person. I can give an example. While he was the Chief Executive Officer of the Municipal Corporation of Kolkata, he had found that there was no Muslim representation in the employment. He made it compulsory that more than 50 per cent of the employment should go to the Muslims because they are part of the country. He had never thought that the minority communities whether a Muslim, a Christian or a Jain, they are anti-national. They are no less national than any* and that was the philosophy which was preached by Netaji Subhas Chandra Bose, unfortunately, this basic fabric of the Indian society, when under attack, does not get any reflection in the President's Address.

We have seen that there are hate speeches. There are congregations wherefrom open declaration of genocide is given and our Prime Minister has not uttered a single word condemning that hatred speech. If this is the person on whom we resorted our responsibility to run the country, we think that we are in danger. Therefore, this Government should come out very clearly as to why should the Supreme Court or the High Court to intervene and ask to initiate action. Why would not the administration on its own take pro-active action? You will be shocked and surprised to know that one of the journalists from a minority community has been chargesheeted because he knows much better. The chargesheet says 'that you are a knowledgeable person and you know much, therefore, you can mislead the people and you go to the jail. Is this the democracy?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, your time allotted has completed. Now, you can conclude, please.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Sir, I will take just one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have one more speaker. So, please.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: I will take just one minute. I will only quote from our first Prime Minister, *Pandit* Jawaharlal Nehru. We should remember every time his views and ideas about the Indian democracy and secularism. He said, "We have definitely accepted democratic process. Why have we accepted it? Well, for a variety of reasons. Because we think that in the final analysis it promotes the growth of human beings--I repeat, it promotes the growth of human beings-- and of society; because, as we have said in our Constitution, we attach great value to individual freedom; because we want the creative and the adventurous spirit of man to grow. It is not enough for us merely to produce the material goods of the world. We do want high standards of living, but not at the cost of man's creative spirit."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: "His creative energy, his spirit of adventure, not at the cost of all those fine things of life….

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Two lines.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, there is a point of order.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Some of the expressions used by...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under which rule? …*(Interruptions)*..

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, under Rule 238, some of the statements made by the hon. Member are very treasonous, disparaging and the entire community....

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, please, I am taking the point of order. ...*(Interruptions)*... Let me take the point of order. ...*(Interruptions)*... Let me take the point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Sir, may I complete my...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is Rule 238, sub-point (vii).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Narasimha*ji*, under Rule 238, which point?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: It is point no. (vii).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under Rule 238, point no. (vii).

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is Rule 238, under (v), sub-point (vii).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, okay, you have made your point, we will examine it. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: He has used defamatory words. He said that any minority person belonging to a minority religion is more patriotic than any* ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, I have noted your point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I think, you cannot make such an atrocious statement. ...*(Interruptions)*...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you have made your point. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: It is atrocious, unacceptable. He must apologize for the remark.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have made your point. Please, please. ...*(Interruptions)*... He has made a point of order. I have noted it. ..*(Interruptions)*... One second. ..*(Interruptions)*... Let me complete. He has made a point of order, I have noted it. If there is anything that should not be there, it will be examined and action be taken.

SHRI ANAND SHARMA: I just want to add one thing. Let it be seen as to what was the quotation of Subhas Chandra Bose and that should be retained in full.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Sir, let me complete. I was not allowed to complete my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. You have ten seconds.

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: I know this will hit somebody because of this because they don't have any idea...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The time now is 2.55 p.m. I will have to close at this point of time. We are already at 2.55 p.m. ...*(Interruptions)*...

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: "..but not at the cost of man's creative spirit, his creative energy, his spirit of adventure; not at the cost of all these fine things of life which have ennobled man throughout ages. Democracy is not merely a question of elections. The question before us is how to combine democracy with socialism, through peaceful and legitimate means." This is the democracy which prompts us to come before this House and which is the obligation of the Government to follow.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you hon. Member. We will now go on to Special Mentions. This discussion will continue tomorrow. Dr. M. Thambidurai, you will be the first person to speak as per the schedule.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): It must not be changed tomorrow. Please allow me to speak first.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Yes. You are on the schedule. You are the first person tomorrow. We will be going on to Special mentions. Due to lack of time, we will be closing at three, we will not be regarding the details. You just have to mention that you are laying it on the Table of the House. Shri Kailash Soni.

SPECIAL MENTIONS

Need to release the remaining quota of urea to Madhya Pradesh

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के रबी सीज़न हेतु 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराने की सहमति दी गई थी और प्रदेश की माँग के विरुद्ध यूरिया उपलब्धता की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है -

1. अक्तूबर-नवंबर : माँग - 13 लाख मीट्रिक टन
   आपूर्ति - 6 लाख 54 हजार मीट्रिक टन (शेष अप्राप्त)

2. दिसंबर : माँग - 5 लाख 1 हजार मीट्रिक टन
   आपूर्ति - 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन।

महोदय, प्रदेश में गेहूं की फसलों की सिंचाई प्रारंभ होने से सभी जिलों में यूरिया की माँग बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अक्टूबर एवं नवंबर माह की शेष मात्रा - 6 लाख 46 हजार मीट्रिक टन यूरिया एवं 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन यूरिया शीघ्र उपलब्ध कराएं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Prof. Manoj Kumar Jha.